HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-31 अक्तूबर, 2019

मिशन रीव के दो वर्ष पूरा होने पर विशेषांक

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2/ अंक 31/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

सपने देखना अच्छा है परन्तु सपनों को पूरा करने के लिए वांछित संघर्ष ही सफलता की कुंजी है ..... डॉ0 एल सी शर्मा

मिशन रीव –एक स्वच्छंद विचार की पौष्टिकता

MISSION RIEV

Ruralising India - Empowering Villages

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief

आम लोगों को परिस्थितिवश या आदतन त्रस्त देखते हुए एक दार्शनिक चिंतन पैदा हुआ कि ऐसा क्या हो कि लोगों को चिंतित नहीं अपितु प्रसन्न देखें। प्रसन्न रहने की जटिलता को समझने के लिए मानव समाज सभ्यता के आरंभ से ही प्रयोगात्मक दृष्टिकोण बनाता रहा। कभी भौतिक संपत्ति के अर्जन में तो, कभी इंद्रियों की पूर्ति में प्रसन्नता का अन्वेषण होता रहा। एक लंबे अंतराल के बाद ऋषि परंपरा ने जन्म लिया तथा सुख के चिरस्थाई स्रोत खोजने पर प्रयोग होते गए क्योंकि भौतिक समृद्धि व इंन्द्रिय सुख क्षणिक साबित हुआ। ऋषियों ने स्थाई आंतरिक सुख व प्रसन्नता की खोज अध्यात्म के रुप में की जिसकी पुष्टि कई युग पुरुषों ने की। श्रीमद्भगवदगीता में श्रीकृष्ण की पुष्टि के अतिरिक्त पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, रामकृष्ण परमहंस, गुरुनानक, कबीर, संत बुल्लेशाह, श्रीराम तीरथ व अन्य युग पुरुषों ने आंतरिक रहस्यों का समय-समय पर उद्घाटन किया। परन्तु यह प्रक्रिया बहुत अनुशासित व दीघ्रगामी है और आज के तीव्रता के युग में यह केवल उन्हीं लोगों की प्राथमिकता बनती है जो ब्रह्मांड के नाटकीय क्रम को समझने लगे हैं। ऐसे बिरले आत्माभिमुख लोगों को छोड़, संसार के सभी व्यक्ति क्षणिक समाधान की तलाश में रहते हैं जिससे उन्हें क्षणिक प्रसन्नता भी मिलती है। इसी प्रकरण को समझकर सभी चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के प्रयोग को मिशन रीव की संज्ञा दी गई। जिसके अंतर्गत व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं व चिंताओं का आकलन कर अपने यथोचित तथा यथासंभव समाधान देने के प्रयास किए जाते हैं। आरंभ में यह महज़ एक खुला विचार था तथा विगत दो वर्षों की ऊंची-नीची यात्रा ने इसे एक स्पष्ट व सटीक यंत्र बना लिया है जहां वास्तव में अब वह यथार्त बनता जा रहा है जो हमने आरंभ में कल्पना की थी। इस दो वर्ष के अंतराल में हमारे 6000 से अधिक सदस्यों ने तथा अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रिय अनुभवों से मिशन की परिपाटी को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभिसिंचित किया। आज अब हम इसके राष्ट्रीय विस्तार पर चिंतन करने के लिए सक्षम हुए हैं। दो वर्ष पूरा करने पर हम मिशन रीव के समस्त सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं को मिशन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

मिशन रीव के दो वर्ष पूरा होने पर कहा 'मिशन रीव है तो संभव है'

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल से सेवा दिल से भुगतान के मूलमंत्र के साथ मिशन रीव ने अपने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य पर आईआईआरडी सेमिनार हॉल में एक कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक एवं मिशन रीव प्रमुख व प्रणेता डॉ० एल सी शर्मा बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में निदेशक सुशमा शर्मा ने भी विशेष रुप से शिरकत की। कार्यक्रम में 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया जिसमें आईआईआरडी से संबद्ध सेवाकर्मी भी शामिल रहे।

विगत दो वर्षों में मिशन रीव ने एक लंबा सफर तय किया है। जन सेवा में हिमाचल प्रदेश के गांव में दस्तक देने के बाद आज मिशन रीव राष्ट्रीय स्तर पर अपने पदचिन्हों के साथ सेवाऐं दे रहा है। इसके साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहना मिली है।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। उसके बाद मिशन रीव के आरंभिक दौर से जुड़े साथियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। इसमें निदेशक सुशमा शर्मा, फ्लायर ग्रुप के सीईओ आन्नद नायर, पूर्व सीईओ मिशन रीव मेहरीन इक़बाल, सी एस अभिमन्यु, सीए शैंकी गुलाटी, एडमिन रीता वर्मा, लीला, दिनेश शामिल थे। सभी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मिशन रीव का विचार डॉ० एल सी शर्मा की उस वृहद् सोच का परिणाम है जिसमें देश भर में ज़रुरतमंद लोगों को घर-द्वार पर ही सेवाओं का निष्पादन करना था। इस व्यापक सोच के बाद इसे अमलीजामा पहनाने की एक बड़ी चुनौती थी जो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िलों में शुरु की गई। उतार-चढ़ाओ के बात मिशन रीव ने अपने दो वर्ष पूरे कर लिए।

मुख्यातिथि एवं मिशन रीव प्रमुख डॉ० एल सी शर्मा ने बताया कि एक सपना जो कि ग्राम स्वराज को लेकर मिलकर देखा गया था उसका प्रारुप ही मिशन रीव है। मिशन रीव का मूल सेवा है तथा लोगों की समस्याओं का समाधान बनना है। मिशन रीव ने गांव-गांव में आम लोगों से सर्वेक्षण के बाद मिशन रीव की नींव रखी और प्रथम संस्करण में इसे कुछ सेवाओं के साथ लोगों तक ले जाने में कुछ हद तक सफल भी रहा। दूसरा संस्करण 'दिल से सेवा-दिल से भुगतान' के मूलमंत्र से आगे बढ़ा जिसमें सदस्यता से लेकर अन्य महत्वपूर्ण बातों पर परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। इन दो वर्षों में मिशन रीव ने अपने 10 प्रभागों में कुछ परिवर्तन करके नए प्रारुप के साथ लोगों के लिए सेवाक्षेत्र में उतरा।

IIHMR UNIVERSITY JAIPUR REVAMPS DEVELOPMENTAL PROGRAMS

After significant contribution in supporting Basic Health Services across country as Indian Institute of Health Management Research (IIHMR), the present form in shape of IIHMR University has been trying evolving as institution of excellence in different fields especially in Developmental Studies. The "07th Board of Studies (BoS)" meeting of the "School of Development Studies (SDS)" at IIHMR University was held on the 15th October 2019, at their Jaipur Campus. SDS currently offers "The MBA Rural Management Advantage" programme, with a curriculum benchmarked according to the recommendations of "International Commission on Education for Sustainable Development Practice" provides A detailed knowledge about four fields viz., "Management, Social Sciences, Health Sciences & Physical Sciences", six field learning segments for a rich blend of theory & "Practice oriented Pedagogy"; Built around a culture of action-oriented research, the university has worked collaboratively with the Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University (USA), as well as international agencies like the "World Health Organization (WHO) & the United Nations (UN)", the school is poised build in a range of niche initiatives towards "Research, Executive Education, Innovation Hub, Online education, Internationalization & Position towards building Policy-Supporting strategic reforms within and aligning with sectoral requirements of strengthening human resources, knowledge management & technical-support";

The High-Level Board included, Prof. Ms. Anuradha S. Palanichamy (Professor & Dean : School of Development Studies, IIHMR University), Shri. Vijay Sardana (Corporate Director & Lawyer specialized in Techno-legal issues including Trade, Investment, IPR & Business), Shri. Hitendra Singh (JSPLS, Ranchi), Shri. Kulbhushan Kothari (Managing Trustee, Pratham (Rajasthan), Prof. Prabal Sen (Professor, Economics Area & Chairperson, Entrepreneurship Development Centre (EDC) at XLRI Jamshedpur), Prof. Pushpendra (Professor & Chairperson, Centre for Development Practice & Research, Tata Institute of Social Sciences, Patna), Ms. Shobhita Rajagopal (IDS, Jaipur), Professor. GyanMudra (NIRD&PR, Hyderabad), and Dr. L.C. Sharma (IIRD, Shimla).

जयपुर में IIHMR के एम बी ए विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए प्रबंध निदेशक डॉ. एल सी शर्मा इसमें ग्रामीण प्रबंधन विषय के अलावा मिशन रीव पर वक्तव्य देकर मार्गदर्शन किया

प्रिय पाठकों !

द रीव टाइम्स के इस अंक में आईआईआरडी के समस्त विकासात्मक कार्यों, गतिविधियों, सेवाओं, और संस्था की बड़ी पहल मिशन रीव के समस्त प्रभागों का विस्तार से वर्णन आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश की अग्रणी संस्था की श्रेणी में आईआईआरडी ने मुक्कमल स्थान पा लिया है जिसके एक वैश्विक प्रयास के अंतर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्र में मिशन रीव ने दो वर्ष भी पुरे कर लिए हैं। आप सभी के सहयोग व स्नेह हेतु समाचार पत्र की ओर से हार्दिक आभार और दीपावली की जगमगाती शुभकामनाऐं।

हेम राज चौहान संपादक द रीव टाइम्स

आईआईआरडी द्वारा देश भर में दी जा रही सेवाएं : एक झलक

करीब 14 साल पहले शिमला के संजौली से एक गैर सरकारी संस्था के तौर पर शुरुआत करने वाला , आईआईआरडी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आईआईआरडी यानि एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। देश की नामी कंपनियों के साथ मिलकर आईआईआरडी देश के 21 राज्यों में विकास की गति को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आईआईआरडी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत सरकार व विभिन्न प्रदेश सरकारों के साथ कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। अगस्त 2018 में ही झारखंड में प्रोजेक्ट रुपांतरण के कार्यान्वयन के लिए संस्था को उत्कृष्ठ संस्था के रुप में सम्मानित किया गया। सितम्बर 2019 में आईआईआरडी लगातार दूसरी बार सीएसआर में नं 1 बेहतरीन ई –शिक्षा प्रणाली में लहराया परचम। आईआईआरडी राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है जो हिमाचल के लिए गौरव का विषय है। हाल ही में आईआईआरडी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से पार्टनरशिप सर्टीफिकेट हासिल किया है। हिमाचल में मिशन रीव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर–द्वार पर विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है।

हमारी सेवाओं की एक झलक

आईआईआरडी ने सीएसआर के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। लगातार दूसरी बार 'सर्वश्रेष्ठ एनजीओ' का खिताब हासिल किया है। संस्था ने इस बार यह उपलब्धि **वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम** के तहत बेहतरीन ई शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में हासिल की है । आईआईआरडी को यह सम्मान दिल्ली में हाल ही में आयोजित '6वें नेशनल सीएसआर सम्मिट, सीएसआर टाइम्स अवार्ड एंड 49वें इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2019' कार्यक्रम मे प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएसआर टाइम्स और इंडियन अचीवर्स फोरम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

आईआईआरडी और एनएसडीसी अब साथ–साथ

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से आईआईआरडी को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसके लिए एनएसडीसी की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब आईआईआरडी एनएसडीसी के साथ मिलकर कौशल विकास में अपना योगदान देगा दे रहा है। अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा चूके हैं।

प्रोजेक्ट रुपांतरण

आईआईआरडी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि उस समय हासिल की जब आजीविका के क्षेत्र में उत्कृष्ठ संस्था के रुप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एंव पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह सम्मान सीएसआर टाइम्स के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2018 के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में आईआईआरडी टीम के साथ संस्था के प्रबन्ध निदेशक डॉ. एल.सी. शर्मा को केन्द्रिय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अलफोंस के. जे. द्वारा प्रदान किया गया। आईआईआरडी ने झारखण्ड के दूरदराज क्षेत्र में आवश्यकता आकलन करने के बाद 2017 में वहां की जनजातीय महिलाओं के लिए 12 विशेष पत्तल बनाने की मशीनों को लगाकर उनके पत्तल बनाने के कार्य को और भी आसान कर दिया।

पेयजल फिल्टर यूनिट

आईआईआरडी की ओर से कनार्टक के चिकबालापुर के आठ गांवों पेयजल से आयन को अलग करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर यूनिट लगाए गए और गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा होशुदया, तिपापुर, विवेकानंद नगर, जिंकेबाचल मजराहोसहाली और चिकातुमुर गांव में भी आर ओर प्लांट लगाकर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में आईआईआरडी ने अहम भूमिका निभाई है। आईआईआरडी द्वारा यमनोत्री, आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल में पेयजल फिल्टर का कार्य प्रगति पर है।

स्मार्ट क्लासरुम

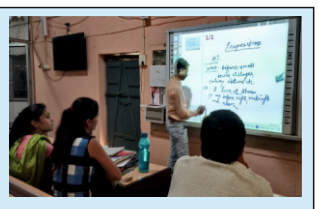

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहल करते हुए आईआईआरडी ने कनार्टक के हुबली में 40 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। इसमें कन्नड़ भाषा में सभी विषयों को डिजीटाइज किया गया। इसके साथ ही इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से इन विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस प्रयास से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ अध्यापकों की अध्यापन क्षमता में भी प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। अभी 40 और विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम में भी आईआईआरडी स्मार्ट क्लासरूम शुरू किये है जिसमे गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।

कुल्लू में बाला कांन्सेप्ट के साथ स्कूल निमार्ण

हिमाचल के कुल्लू जिला में मनाली के ब्लॉक नग्गर की ग्राम पंचायत हालम में राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरसई के स्कूल भवन का निर्माण किया गया। स्कूल के लिए दो मंजिला भवन का निर्माण किया गया। इस भवन में बाला कांन्सेप्ट के साथ प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए आकर्षक मॉडल बनाए गए ताकि बच्चे खेल–खेल में पढ़ना सीख सके। इसके अलावा इस स्कूल में छात्रों के मनोरंजन के लिए भी ऐसे मॉडल बनाए गए हैं जिसमे मनोरंजन के साथ बच्चों की बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो सके।

आईआईआरडी द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

प्रोजेक्ट	राज्य
रूपांतरण	झारखण्ड
पेयजल फिल्टर यूनिट	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखण्ड,बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, यमनोत्री
स्मार्ट क्लासरूम (ई-शिक्षा प्रणाली)	कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम
कुल्लू में बाला कांन्सेप्ट के साथ स्कूल निमार्ण	हिमाचल प्रदेश
आईपीडी शोली सोलर लाइट	हिमाचल प्रदेश
बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम	कर्नाटक
शौचालय निर्माण	बिहार, कर्नाटक, आसाम, पश्चिम बंगाल,यमनोत्री
बंगलुरू में स्टील बिन इंस्टालेशन	कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश, यमनोत्री
समुदाय सहभागिता कार्यक्रम	आसाम
कौशल विकास कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश
डीडीयू -जीकेवाई	उत्तर प्रदेष
कौशल विकास कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश (शिमला)
बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम	उड़ीसा
कूड़ा-कचरा प्रबंधन के लिए डम्पर/टिपर उपलब्ध करना	चण्डीगढ़
प्रोजेक्ट जनऔषधि केंद्र	हिमाचल प्रदेश
कोल बांध समाजिक प्रभाव मूल्यांकन	हिमाचल प्रदेश

बिहार, कर्नाटक, यमनोत्री, आसाम एवं पश्चिम बंगाल में शौचालय निर्माण

आईआईआरडी कनार्टक और बिहार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के ईस्ट चंपाराण और कर्नाटक के चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

कनार्टक, हरियाणा, मध्यप्रदेश में स्टील कूड़ेदान लगाने का कार्य

आईआरडी कनार्टक की राजधानी बंगलुरू में विभिन्न स्थानों पर स्टील बिन यानि स्टील से बने कूड़ेदान लगाने का कार्य सम्पन कर चूका है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 10 हजार स्टील बिन लगाने का कार्य आईआईआरडी कर रहा है। आईआईआडी ने यमनोत्री चण्डीगढ़ में भी स्टील कूड़ेदान लगाए है।

डीडीयू–जीकेवाई यूपी

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आईआईआरडी द्वारा यूपी के चंदोली और कासगंज केंद्रो पर 380 अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों को जरदोजी वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सोने और चांदी से की जाने वाली कढ़ाई का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके पूरा होते ही इन अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट भी कौशल के आधार पर आईआईआरडी की ओर से की जाती है।

उत्तराखंड में पीएमकेवीवाई

पीएमकेवीवाई प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार और पौड़ी में आईआईआरडी कंप्यूटर और सिलाई मशीन ट्रेड्स में प्रशिक्षण दे रहा है।

शिमला में कौशल विकास कार्यक्रम

जिला शिमला में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत पांच केंद्रों पर कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आईआईआरडी को अधिकृत किया गया है। इनमें शनान, रोहड़ू, कुमारसैन, ननखड़ी (शोली) और सुन्नी शामिल है।

उड़ीसा में बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम

उड़ीसा के बरूनी में पीआर हाई स्कूल फील्ड में भी आईआईआरडी की ओर से एक बहुउदेशिय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, यह स्टेडियम अति आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

कोल बांध सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन

आईआईआरडी की ओर से कोल डैम प्रोजेक्ट के प्रभाव को लेकर मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। आईआईआरडी द्वारा हिमाचल के उन चार जिलों में इस प्रोजेक्ट के समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है जो इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। इसमें शिमला, सोलन, बिलासपुर और मंडी शामिल है।

आईपीडी शोली सोलर लाइट

शिमला में रामपुर के तहत आने वाली शोली पंचायत प्रदेश की ऐसी पहली पंचायत है जहां पर सौ फीसदी सोलर लाइट्स की व्यवस्था की गई है। एकीकृत पंचायत विकास शोली प्रोजेक्ट के तहत आईआईआरडी ने शोली पंचायत में 350 सोलर लाइट्स लगाई है। इन लाइट्स की देखभाल का जिम्मा भी आईआईआरडी ही संभाल रहा है।

कर्नाटक में बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर दूसरे राज्य में भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आईआईआरडी के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आ रही है। इसका ताजा उदाहरण आईआईआरडी की ओर से बनाया जा रहा बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम है। जो कर्नाटक के धारवाड़ में बनाया जा रहा है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कांपलैक्स में युवाओं और अन्य आयुवर्ग के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों की सुविधा होगी और साथ ही फिट रहने के लिए जिम और अन्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण भी होंगे। इस बहुउद्देशिय इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास पैट्रालियम एवं प्राकृतिक गैस स्थाई संसदीय समिति के अध्यक्ष प्रह्लाद जोशी ने अक्तूबर 2018 में किया।

आसाम में समुदाय सहभागिता कार्यक्रम

आसाम में समुदाय सहभागिता कार्यक्रम के तहत आईआईआरडी प्रदेश के आठ जिलों में इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में इन आठ जिलों के लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और विभिन्न योजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को लेकर कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम

भारत सरकार की कौशल विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर आईआईआरडी अलग–अलग ट्रेड्स में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर अभ्यर्थियों को रोजगार से भी जोड़ रहा है। इन केंद्रों में यूपी के चंदोली, कासगंज, गोरखपुर, महाराजगंज, दिओरिया और खुशीनगर केंद्र शामिल है।

प्रोजेक्ट जनऔषधि केंद्र

आईआईआरडी को बीपीपीआई की ओर से तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों को ऐसे स्थानों पर खोला जा रहा है जहां पर ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जनऔषधि केंद्रों पर लोगों को बेहद सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता आईआईआरडी की ओर सुनिश्चित करवाई जा रही है। जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज काफी सस्ता हो गया। इससे पहले लोगों के पास सस्ती दवाईयों का कोई विकल्प नहीं था और उन्हें मजबूरन महंगी दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। लेकिन आईआईआरडी की ओर से खोले जा रहे जनऔषधि केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है। हिमाचल में अभी तक शिमला, कुल्लू , मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में विभिन्न स्थानों पर जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और जल्द ही अन्य जिलों में भी जनऔषधि केंद्र खोले जाएंगे।

रीव क्लिनिक

शिमला में प्रदेश का पहला रीव क्लिनिक खोला गया जहां अधिकतर टेस्ट की सुविधा के साथ उपचार भी संभव हो पाया है। शीघ्र ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी रीव क्लिनिक खाले जाएगें।

शिक्षा और प्रशिक्षण प्रभाग

मिशन रीव के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रभाग शिक्षा का है जिसमें वृहद् प्रारूप में लोगों को इसमें संबद्ध किया गया है । शिक्षा के क्षेत्र में समस्त पहलुओं को इसमें समाहितकिया गया है। शिक्षा का स्तर हालांकि दस्तावेज़ों में बेहतर है लेकिन ज्ञान का क्षेत्र अभी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है । यानि शिक्षा को पढ़ाई के अलावा ज्ञान से जोड़ना भी आवश्यक है जिसके लिए मिशन रीव में सार्थक प्रयास किया गया है ।

शिक्षा और प्रशिक्षण प्रभाग के अंतर्गत सेवाएं

- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि समस्त विषयों पर ऑनलाईन कोचिंग दी जा रही है ।
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था और व्यस्क आयुवर्ग आधार पर परामर्श
- ई-लर्निंग उपकरणों एवं अन्य तकनीक का समावेश

विदेशों में पढ़ाई के लिए सेवाऐं

उदाहरण के लिए आवश्यकता आकलन में जब शिक्षा से संबद्ध प्रश्नों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है तो उसमें विदेशों में पढ़ाई को लेकर यदि कोई सेवाओं को चाहता है, उसके लिए मिशन रीव विदेशों में अच्छे विश्वविद्यालयों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी और दाखिले तक समस्त सेवाओं को प्रदान करता है ।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति

इसके लिए मिशन रीव उन संस्थानों की सूची तैयार करता है जिसमें छात्रवृति योजना को लागु किया गया है तथा उनके लिए फॉर्म आदि भरना ये सब औपचारिकताओं को इसी प्रभाग में पूरा किया जाता है ।

ऑनलाइन उच्च शिक्षा की सुविधा

यदि विद्यार्थी घर से ही पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाईन पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस सुविधा के लिए इसी प्रभाग में मिशन रीव सेवाऐं प्रदान कर रहा है । इसके लिए फॉर्म पर जो भरा गया है उसका आकलन करके समस्त औपचारिकताओ को पूरा किया जाता है । समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद सेवाऐं प्रदान की जा रही है ।

शैक्षणिक संस्थान में दाखिला हेतु सेवाऐं

यदि किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले से संबन्धित जानकारी और सहायता की आवश्यकता है तो मिशन रीव इसी प्रभाग में वांछित शिक्षण संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर दाखिले एवं शुल्क आदि से जुड़ीं समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

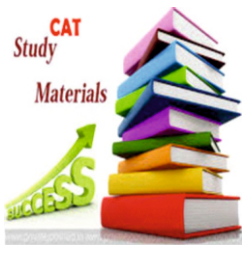

पठन सामग्री सहयोग सेवा

यदि कोई भी घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सामग्री सेवा सहयोग चाहता है तो मिशन रीव द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरने के बाद समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबन्धित पठन सामग्री उपलब्ध करवाने में सहयोग देता है । इसके अलावा समस्त गतिविधियों एवं क्रियाकलापों पर निगरानी भी की जाती है ।

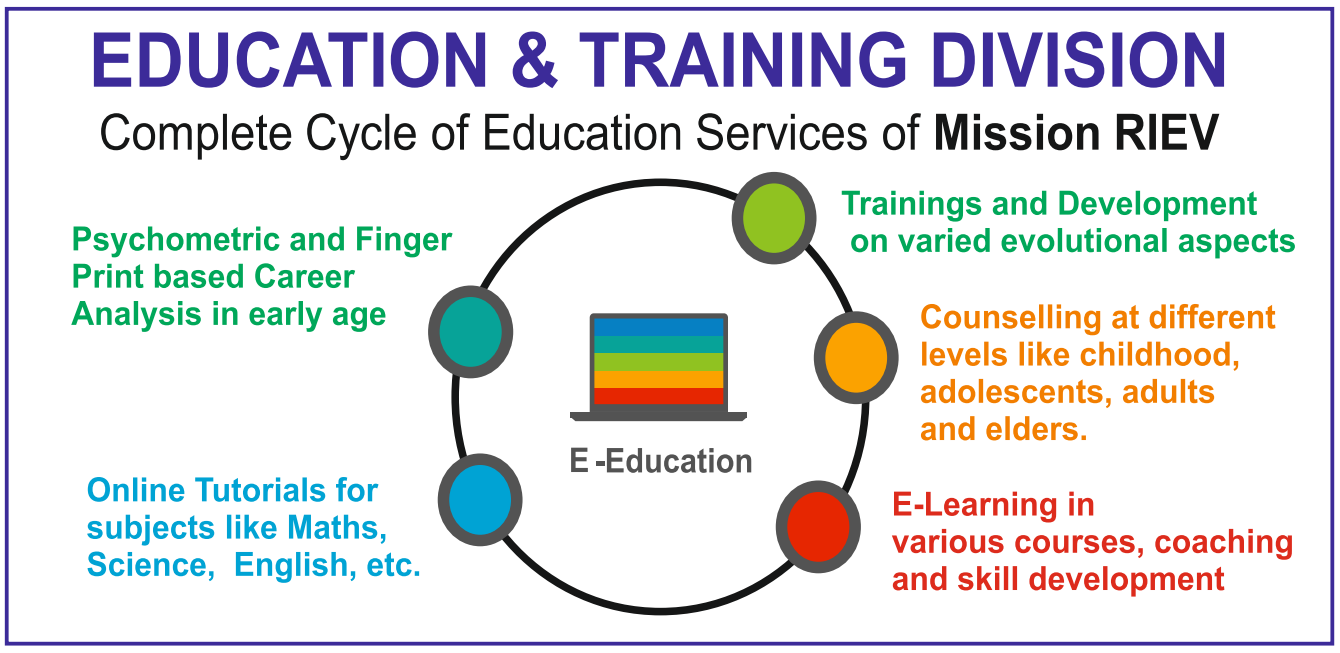

ई-लर्निंग शैक्षणिक सेवाऐं

आवश्यकता आकलन में यदि कोई भी परिवार का सदस्य यानि पढ़ने वाले घर पर ई-लर्निंग सेवा चाहते हैं तो मिशन रीव इसके लिए इसी प्रभाग के अंतर्गत वांछित सेवा को प्रार्थी तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है । यह समस्त जानकारियों प्रभाग प्रमुख से साझा की जाती है । उसके बाद निगरानी भी की जाती है कि प्रार्थी को ई-लर्निंग सामग्री उचित प्रकार से पहुंच भी रही है कि नहीं । सदस्यों के साथ यूजर और पासवर्ड आदि साझा किया जाता है ताकि उनके लिए अन्य सुझावों आदि पर सहयोग दिया जा सके ।

करियर सूचना सेवाऐं

सदस्यों को समय-समय पर नौकरियों और संबन्धित जानकारी के लिए संदेश अलर्ट आदि की सुविधा के लिए मिशन रीव सेवाऐं देता है । इसके लिए रीव द्वारा निर्धारित फॉर्म पर वांछित जानकारी पर ही कार्य किया जाता है । जानकारी को प्रभाग प्रमुख से साझा किया जाता है । इस बात की समय-समय पर जांच की जाती है कि क्या सदस्य को उनके मोबाइल या अन्य सोशल लिंक पर जॉब अलर्ट आदि प्राप्त हो रहे हों । अन्य सोशल मीडिया में मेल, व्ट्सअप आदि शामिल है ।

करियर परामर्श सहयोग सेवा

सदस्य यदि विभिन्न स्ट्रीम में जानकारी व जॉब से संबन्धित परामर्श आदि चाहते हैं तो इसके लिए प्रभाग प्रमुख से सूचना को साझा करने के बाद सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है । साथ ही परामर्श के लिए मिशन रीव उत्कृष्ठ सेवाओं के साथ सदस्य तक पहुंचता है ।

IIRD के प्रशिक्षु एवं अधिकारी योगी जी के साथ

आवश्यकता आकलन का प्रारूप नमूना

हमारा लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को उत्कृष्ठता के साथ ऑनलाईन सेवाओं के माध्यम से सदस्य तक पहुंचाने की है । ऐसा कोई भी क्षेत्र जो शिक्षा से संबन्धित हो उसे मिशन रीव के इस प्रभाग में शामिल किया गया है ।

क्या आप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृति के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के बारे में मार्गदर्शन चाहते हैं? Do you want guidance regarding admission in foreign universities through various international scholarships?	○ Yes	○ No
क्या आप विश्वविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में मार्गदर्शन चाहते हैं, और भारत में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न छात्रावृति के बारे में जानने में सहायता चाहते हैं? Do you want guidance regarding admission in universities, and want assistance in knowing about various scholarship for higher education in india?	○ Yes	○ No
क्या आप पत्राचार पाठयक्रम के विकल्प या घर से अध्ययन करने के विकल्प के वारे में जानना चाहते हैं? Do you want to know about the options of a correspondence course or the option to study from home?	○ Yes	○ No
क्या आपके परिवार में किसी को उच्च शिक्षा के लिए किसी संस्थान में प्रवेश पाने में सहायता की आवश्यकता है? Does anyone in your family need assistance in getting admission in an institution for higher education?	○ Yes	○ No
क्या आपके घर में किसी को प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है? Does anyone in your homr need omline study material for competitive exams?	○ Yes	○ No

वर्तमान में क्या

मिशन रीव ने वर्तमान में ऑनलाईन ई-शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान करने की ओर क़दम बढ़ाया है । गणित आदि विषयों के साथ विद्यार्थियों तक गुणवत्ता आधारित सेवाऐं प्रदान की जा रही है । कौशल विकास प्रशिक्षण मे भी ऑनलाईन ई-शिक्षा के तहत सेवाएं दी जा रही है।

स्वास्थ्य प्रभाग

प्रदेश के गांवों में लोगों के जीवन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिशन रीव के तहत बनाए गए 10 प्रभागों में से स्वास्थ्य प्रभाग एक है। करीब दो साल पूर्व जारी एक स्वास्थ्य रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल के बाद हिमाचल का दूसरा स्थान हैं। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते गांव में रहने वाले लोगों को तक इन स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। इसी समस्या से निपटने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत गांव के लोंगों को घर – द्वार पर सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य प्रभाग बनाया गया। इस प्रभाग के तहत गांवों में लोगों को उनके घर तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहें हैं कि मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य प्रभाग कैसे काम करता है और कैसे आप इस प्रभाग का हिस्सा बनकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

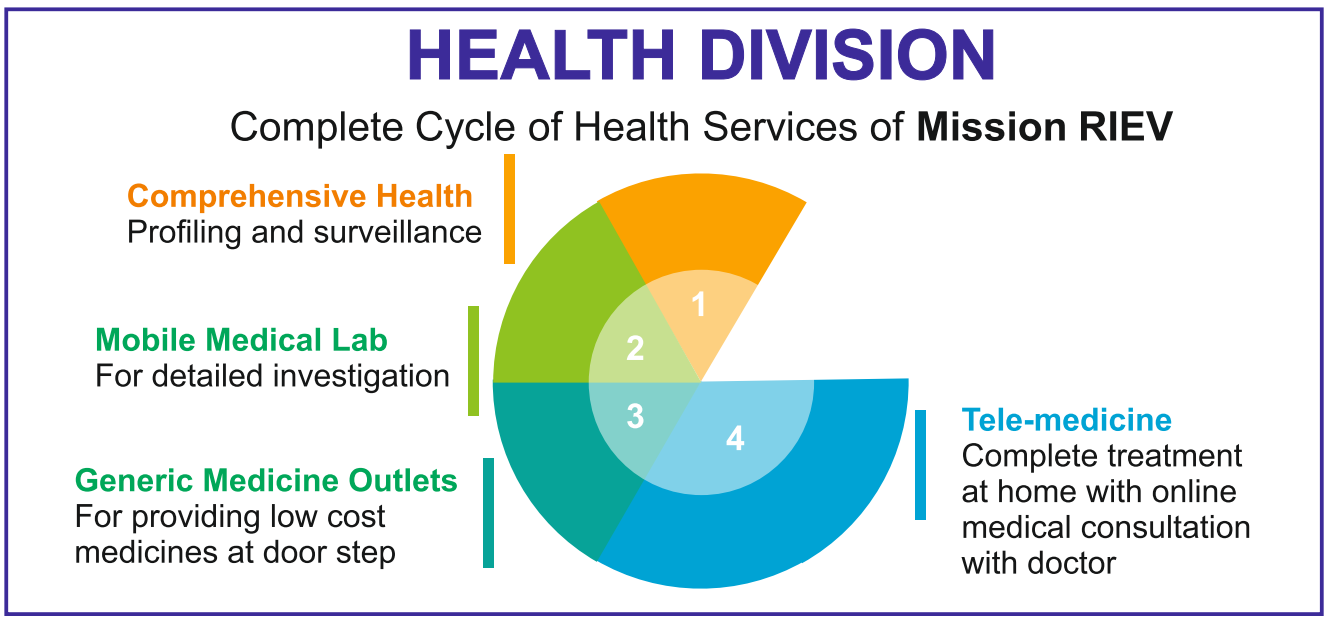

ऐसे जुड़ें स्वास्थ्य प्रभाग से

अगर कोई भी व्यक्ति मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो सबसे पहले उसे मिशन रीव सदस्यता के तीन विकल्पों में से एक विकल्प के आधार पर सदस्यता लेनी होगी। यह सदस्यता मिशन रीव ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ली जा सकती है। इसके बाद सदस्य बनते ही आपके सामने मिशन रीव के तहत दी जाने वाली सेवाओं की सूची प्रभाग के आधार पर आपके सामने होगी। इसमें प्रभाग का चयन कर आपको इससे बेहद सरल प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दरअसल मिशन रीव के पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद स्वास्थ्य प्रभाग के लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। इस पश्नोत्तरी के तहत व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर मिशन रीव के तहत सेवाएं भी प्रदान की जाती है।

इन सेवाओं से हुई शुरुआत

जनऔषधि केंद्र

गांव के लोगों को कम दाम पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए 15 जुलाई 2018 को प्रदेश में जनऔषधि केंद्र खोलने का सिलसिला

आईआईआरडी शिमला से शुरू हुआ। इस शुरूआत के साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और अध्याय जुड़ गया। उस दौरान तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और वर्तमान मुख्यसचिव हिमाचल प्रदेश सरकार बीके अग्रवाल ने आईआईआरडी कार्यालय से पांच जनऔषिधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसमें मंडी में भगरोटू और छतरी, कांगड़ा में नूरपुर और पालमपुर तथा हमीरपुर का जाहू केंद्र शामिल है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनऔषिधि केंद्र खोले गए। इनमें चंबा के दूरदराज के इलाकों को भी प्राथमिकता दी गई। इसी तरह कुल्लू के हाथी थान समेत प्रदेश के कई स्थानों जनऔषिधि केंद्र खोले गए।

रीव टेलीमेडिसन

जन स्वास्थ्य एवं सुगम, सुलभ व सस्ता उपचार की प्राथमिकता पर केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मिशन रीव ने स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरे हिमाचल में लोगों तक पहुंचाने तथा अपनी ही तरह की पृथक एवं नई पहल टेलीमेडिसन को जन-जन तक अति सरल व ऑनलाईन स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु आरम्भ किया है।

ऐसे काम करती है मिशन रीव टेलीमेडीसन

टेलिमेडीसन प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल में कोई भी पंजीकृत चिकित्सक अपना पंजीकरण करवा सकता हैं। इसके लिए डॉक्टर को वेबपोर्टल (www. telemedicine.missionriev.in) पर लॉगइन कर अपना पंजीकरण समस्त दस्तावेज़ी औपचारिकताओं एवं प्रमाणिकता के साथ करना हैं। चिकित्सक के पंजीकरण की पुष्टि मिशन रीव सचिवालय से की जाती है तथा उन्हें आईडी दी जाती हैं।

उसके बाद गावं-गांव में स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से लोगों की जांच का सारा विवरण स्वास्थ्य मोबाईल लैब में जाता हैं और स्वास्थ्य मोबाईल लैब में जांच के उपरांत रिपोर्ट उसी वेबपोर्टल पर डॉक्टर के पास स्वतः रिकॉर्ड में आ जाता हैं। जैसे ही डॉक्टर अपनी आईडी से लॉग इन करते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूरा विवरण पोर्टल पर आ जाता हैं।

यहां देखी जा सकेगी पेशेंट हिस्ट्री

डॉक्टर जांच के परिणामों का अध्ययन कर आगामी चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार हेतु ऑन लाइन प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानि व्यक्ति की जांच के

परिणामों में यदि उसे उपचार की आवश्यकता हैं और कोई दवाई देनी हैं तो संस्था के पोर्टल पर ही सारी दवाइयों का विवरण उपलब्ध हैं। डॉक्टर द्वारा एक क्लिक पर ही संबन्धित दवाईयों को निर्धारित कर चयनित कर लिया जाता हैं। पोर्टल पर ही दवाईयों को किस प्रकार और कितने समय में लेना हैं, क्या खाना है, क्या परहेज़ करना है, यह डाइटचार्ट आदि डॉक्टर ऑनलाइन ही भरेंगें।

एक क्लिक पर ही दवाईयों की लिस्ट

पोर्टल पर समस्त दवाईयां मात्र एक क्लिक से ही देखी और मरीज़ को लिखी जा सकती हैं। ये सभी दवाईयां जेनेरिक हैं व अन्य किसी भी ब्रांड की दवाईयों से दाम कम हैं और मिशन रीव द्वारा संचालित जेनेरिक औषधि केन्द्रों पर सुगमता से उपलब्ध है।

सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसकी ऑनलाईन प्रमाणित प्रति मोबाईल लैब, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, ज़िला कॉर्डिनेटर और पंचायत फेसिलिटेटर के पास भी उपलब्ध हो जाती है। जांच और डॉक्टर के परामर्श एवं देखरेख के बाद रीव पंचायत फेसिलिटेटर संबन्धित व्यक्ति के पास जाकर उसे डॉक्टर द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं उपचार की जानकारी घर पर ही देते हैं।

रीव के जनऔषधि केन्द्रों से सस्ती दवाईयों को उपलब्ध करवा कर उपचार आरम्भ हो जाता हैं तथा समस्त चिकित्सीय सलाह और जानकारी की लिखित प्रतिलिपि मरीज़ को दी जाती हैं।

सेहत का निरीक्षण

एक निर्धारित समय के बाद डॉक्टर मरीज़ के उपचार की देखरेख ऑनलाईन ही करते हैं क्योंकि 10 या 15 दिनों के बाद पुनः स्वास्थ्य सेवक मरीज़ की जांच करते हैं। डॉक्टर को इसकी पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ऑनलाईन परामर्श देने की सुविधा हो जाती हैं। यदि मरीज़ को दवाईयों के अलावा भी बीमारी की बढ़ रही गंभीरता से दो-चार होना पड़ रहा हैं और उसे उपचार और गहन व विस्तृत जांच की आवश्यकता हैं तो डॉक्टर राज्य अस्पतालों के लिए भेजने का परामर्श देते हैं।

आईआईआरडी में खुला रीव क्लीनिक

ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आईआईआरडी शनान में एक साल पूर्व रीव क्लीनिक खोला गया। इस क्लीनिक में विभिन्न तरह के टेस्ट कराने की सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य परामर्श भी लोगों को दिया जा रहा है। इस क्लीनिलक से संजौली मल्याना, शनान व पंथाघाटी के आसपास के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। शनान में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर चैकअप करने के लिए भी डीडीयू या संजौली जाना पड़ता था। लेकिन अब शनान में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से काफी आराम है। रीव क्लीनिक के साथ ही यहां पर जनऔषधि केंद्र भी है। इस केंद्र में दवाईयां बाजार से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

आगे क्या

पंचायतों में ऑनलाइन हैल्थ कंसल्टेंसी- मिशन रीव के तहत हर पंचायत में लोगों को ऑनलाइन हैल्थ कंसल्टेसी सर्विस देने की भी योजना है। यानी लोग अगर किसी साधारण अथवा गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं अथवा किस रोग से कैसे बचा जा सकता है, यह जानना चाहते हैं तो वह अपने सवालों का जवाब मिशन रीव के विशेषज्ञों से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फिट रहने के लिए डाइट प्लान, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास से जुड़ी अन्य जानकारी आदि के बारे में भी लोग ऑनलाइन ही सलाह ले सकेंगे।

तैयार होगा हैल्थ डेटा

मिशन रीव के तहत जो भी मरीज स्वास्थ्य प्रभाग के तहत पंजीकृत होगा, उसकी एक अलग हिस्ट्री तैयार होगी। यह डेटा आने वाले समय में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनने वाली नीतियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि हमारे पास पूरे प्रदेश के लोगों की सेहत को लेकर डेटा होगा। इस डेटा के आधार पर यह तय करना आसान होगा कि किस तरह के रोगों के निवारण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह का है।

नशे के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई - पिछले कुछ समय से हिमाचल में नशे का प्रचलन काफी बढ़ गया है। खासकर युवा पीढ़ी को नशे की लत तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। इस समस्या से निपटने के लिए मिशन रीव की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में नशे के खिलाफ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक और पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

आवश्यकता आकलन का प्रारूप नमूना

क्या आप दवाओं पर खर्च कम करना चाहते हैं और उपने घर पर सस्ती जेनेरिक दवाएं चाहते हैं? Do you wish the reduce the expenditure on medicines and want affordable generic medicines at your home?	○ Yes ○ No
क्या आप अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा चाहते हैं? Would you like facility of receiving SMS alert regarding your health issues?	○ Yes ○ No
क्या आपको अपने घर पर बुनियादी सस्ती स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए सुविधा की आवश्यकता हैं? Do you need support for getting basic affordable health checkups done at your home?	○ Yes ○ No
क्या आप हमारी ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्राप्त करना चाहेंगे ? Would you like to get our online health consultancy service?	○ Yes ○ No
क्या आप अपने अंगों को दान करने के लिए पंजीकृत होना चाहते हैं? Would you like to get registered for donating your organs?	○ Yes ○ No

SUBMIT

एकीकृत जोखिम तथा सामाजिक सुरक्षा प्रबन्धन प्रभाग

ऐसी सभी विपदाऐं और आकस्मिक घटनाऐं जो पूर्व निश्चित नहीं होती और जिन पर इंसान का कोई भी नियंत्रण न हो, वो सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। यह सरकार की जिम्मेवारी का भाग है कि वो आम जन को इस प्रकार की विपदाओं/आपदाओं से सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबन्ध करें। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्रारंभिक मूल में सामाजिक सुरक्षा आती है।

मिशन रीव के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में दी जा रही सेवाऐं

- आपातकालीन सहयोग सेवाऐं
- वृद्धावस्था में सहयोग सेवाऐं
- बीमा सहयोग सेवाऐं
- जीवन बीमा योजना सेवाऐं
- जनरल बीमा योजना सेवाऐं
- प्रत्यारोपण सहयोग सेवाऐं
- अक्षमता/दिव्यांग सहयोग सेवाऐं
- पेंशन सहयोग सेवाऐं
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- स्वास्थ्य बीमा योजना सेवाऐं

आपातकालीन सहयोग सेवा

आवश्यकता आकलन में यदि आपदा या आपातकालीन स्थिति में यदि सेवाओं की आवश्यकता है तो इसके लिए मिशन रीव उस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम के सहयोग से सेवाऐं प्रदान करता है।

आपदाऐं विभिन्न प्रकार की हो सकती है

- स्वास्थ्य संबन्धी आपातकालीन स्थिति
- प्राकृतिक आपदा
- सामाजिक मुद्दे
- और वो समस्त प्रकार की घटनाऐं/दुर्घटनाऐं जिनमें तुरंत राहत सेवाओं की आवश्कता हो

मिशन रीव को विकट परिस्थिति में करना क्या है ?

ऐसी स्थिति में जब कोई आपदा में मिशन रीव से सहयोग मांगे तो

- मिशन रीव टीम को मानसिक रुप से तैयार रहना होगा तथा सही जानकारी एवं सहायता के साथ दुर्घटना से प्रभावितों तक पहुंचना है तथा आवश्यक क़दम जो उठाने पड़े उसके लिए प्रयास करना।
- कोई भी क़दम उठाने या संबन्धित अधिकारियों तक बात करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इसकी जानकारी 112 आपातकालीन सेवा नंबर पर दी जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में सूझबूझ के साथ पेश आया जा सके।
- ऐसी स्थिति में ही यह सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि यह आग, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा है और उसी हिसाब से सेवाओं कर वितरण संभव हो सकता है।
- सेवाओं और अन्य सहायता के बाद भी मिशन रीव के सदस्यों की उस आपदा में उपस्थिति पीड़ित के लिए मनोबल एवं सहारा होती है।
- इस बात की तसदीक करना आवश्यक हो कि बुजुर्गों और पीड़ितों का प्राथमिकीकरण करके सेवाऐं प्रदान की जाए यानि जिसे सबसे अधिक आवश्यकता है उसे पहले सेवा मिले।
- मौके पर टीम लोगों का सहयोग भी लेगी ताकि सेवाओं की त्वरिता को सुनिश्चित किया जा सके।

बुजुर्गों के लिए सेवाऐं

- भारतवर्ष में 11 करोड़ से अधिक की आबादी 60 वर्ष हैं या इससे अधिक की आयु की है।
- जिन बुजुर्गों ने इस आयु तक बहुत कठिन परिश्रम करके जीवनयापन किया है उन्हें उनके बच्चों और रिश्तेदारों की बेरुखी और अपने जीवन को स्थायित्व देने के लिए अलग रहने के कारण अकेलापन और घुटन का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा भी यदि ये बुजुर्ग परिवार के साथ भी रहते हैं तो भी उन्हें बाहरी सहयोग की आवश्कता रहती है जिसको मिशन रीव के इस प्रभाग में पूरा करने के लिए सेवाऐं दी जाती हैं।
- टीम को ग्राम पंचायतों एवं अन्य सामाजिक संगठनों की सहायता से इन बुजुर्गों के लिए सहयोग की योजना पर कार्य करना होता है ताकि उचित प्रकार से सेवाओं को प्रदान किया जा सके।
- इसके लिए मिशन रीव टीम पंचायत आदि से मिल कर ग्रामीण स्तर पर ही सामुदायिक संबद्ध कार्यक्रमों और योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे बुजुर्ग अपने साथियों के साथ मिलते हैं तथा अपनी बातों को साझा करते हैं।

ज़रूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा का तानाबाना आर्थिक सुरक्षा पर भी निर्भर है। इसलिए उनको पेंशन योजना से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके।
- मिशन रीव के सेवाकर्मीयों के पास सरकार एवं निजी आर्थिक संस्थानों की अनेकों पेंशन योजनाऐं उपलब्ध है जिसे लाभार्थियों को दिया जा सकता है:

1. पेंशन योजनाऐं जो कि जोख़िम सहायता भी प्रदान करती है बुजुर्गों के लिए
2. दिव्यांग/ शारीरिक रुप से अक्षम
3. विधवा
4. अविवाहित महिलाओं के लिए
5. उन बच्चों के लिए पेंशन जिन्होंने अपने संरक्षकों को नौकरी के दौरान खो दिया

- मिशन रीव सेवाकर्मी को आवश्यकता है स्वयं को अपडेट रखते हुए विभिन्न प्रकार की पेंशन सेवाओं को जानने और उन्हें ज़रुरतमंद लोगों तक ले जाने की जिसमें उत्कृष्ठ सेवाओं के साथ मिशन रीव प्रदान कर रही है।

बीमा सहायता

मिशन रीव इन सेवाओं में सहयोग दे रही है :

- प्रोपर्टी या फसलों के नष्ट हो जाने पर बीमा सेवाऐं
- बीमा दावा/claim सेवाऐं
- जीवन बीमा योजना सेवाऐं
- जनरल बीमा योजना सेवाऐं
- स्वास्थ्य बीमा योजना सेवाऐं

1. मिशन रीव सेवाकर्मी लोगों को उत्कृष्ठ सेवाओं की जानकारी और बीमा योजना पर जानकारी देगा तथा अन्य सहायता भी प्रदान करेगा।
2. यदि बीमा दावों में कोई दिक्कत आ रही हो तो सेवाकर्मी इसमें समाधान के लिए उचित सहयोग करेगा।
3. सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए लोगों को एल आई सी की उत्कृष्ठ सेवाओं से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास किए जाते हैं।

शारीरिक रुप से अक्षम / दिव्यांगों के लिए सेवा / सहयोग

- किसी भी कारण से शारीरिक रुप से अक्षमता किसी बड़ी विपदा से कम नहीं होती
- उन्हें भी जीवन को सम्मानजनक और प्रसन्नता से जीने का अधिकार हैं लेकिन कई बार विवषता इतनी होती है कि ऐसा संभव नहीं हो पाता है।
- उनकी इसी विवशता को ध्यान में रखते हुए मिशन रीव एक सहयोगी की भूमिका में है तथा सहायता के लिए हाथ बढ़ाकर हम उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
- इस सेवा के अंतर्गत मिशन रीव विभिन्न प्रकार से अपनी सेवाओं को उनके लिए प्रदान कर सकता है जैसे कि :

1. उनके लिए स्वास्थ्य बीमा में सहयोग करना
2. सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने में सहयोग करना
3. कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी आवश्यकता आधारित सहायता करना।

जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रयास

प्रत्यारोपण सहयोग सेवा

- जिस व्यक्ति को शरीर के किसी भी अंग के प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, उसके लिए मिशन रीव सेवाकर्मी इसी प्रभाग के अंतर्गत समय सीमा में इसके प्रबंधन में सेवाऐं दे रहे हैं।
- रीव सेवाकर्मी संबन्धित अस्पतालों से संपर्क करके आवश्यक मेडिकल औपचारिकताओं को पूरा करते हैं तथा जानकारी भी प्राप्त करके लाभार्थी को प्रदान करते हैं।
- मिशन रीव इस प्रभाग के अंतर्गत हरसंभव कोशिश कर रहा है ताकि किसी का जीवन बचाने में अपनी सार्थक भूमिका सामने रखे।

मिशन रीव सलाहकार बोर्ड का गठन

- आपदा जोख़िम के ख़तरों से निपटने के लिए समाज के जागरुक नागरिक मिशन रीव सलाहकार बोर्ड से जुड़कर पंचायत स्तर से सहयोग कर सकते है।
- सलाहकार बोर्ड का गठन आई आई आर डी के तत्वावधान में हुआ है तथा सामाजिक विकास के लिए जो भी स्वैच्छिक सेवाऐं प्रदान करना चाहता हो, उसे इसमें जुड़ने के लिए मिशन रीव ने अवसर प्रदान किया है।
- सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को ये अधिकार और गर्व का विषय होगा कि वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों, गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं।
- किसी भी गतिविधि और आपदा के समय अथवा संस्था के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
- पंचायत स्तर पर जुड़कर जल प्रबंधन, वनीकरण, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन में सहयोग किया जा रहा है।

आपदा जोख़िम कम करने के लिए

- मिशन रीव किसी भी अप्राकृति आपदा के समय, दुर्घटना अथवा अन्य गंभीर स्थिति में जो कि मानव जनित हो या प्राकृतिक, में सेवाऐं देने के प्रति संकल्पबद्ध है।
- सामाजिक गंभीर मुद्दों पर मिषन रीव बड़े अभियान चलाकर लोगों को जागरुक कर रहा है तथा समाधान के लिए भी प्रयासरत है। इसका बड़ा उदाहरण नशामुक्त अभियान है जिसे 75 लाख से अधिक की आबादी वाले हिमाचल में प्रत्येक ज़िले में सफलतापूर्वक चलाया गया।
- हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा में एक बड़ी आपदा में मिशन रीव ने ऐतिहासिक पहल करते हुए सैंकड़ों लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए सराहनीय प्रयास किया।
- किसी भी आपदा की स्थिति में मिशन रीव और सलाहकार बोर्ड मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एक बड़ी सामाजिक जिम्मेवारी में साझा प्रयास कर सकते हैं जेसा कि हो भी रहा है।

उपलब्धि

चंबा में रेबिज़ से बचाव में मिशन रीव के इसी प्रभाग ने दी सराहनीय सेवा

- चंबा ज़िला के थल्ला गांव में 2018 में रेबिज़ से बचाने में मिशन रीव ने आपात सेवाऐं प्रदान की जिससे बड़ी महामारी होने से बच गई।
- एक परिवार की गाय को रेबिज़ संक्रमित कुत्ते ने काट लिया तथा वो परिवार उसका दूध पी रहा था साथ ही पूरे गांव में दूध का वितरण भी किया। इतना ही नहीं उस दूध को गांव के एक कार्यक्रम में धाम में भी उपयोग में लाया गया जिसमें आस-पास के गांव के लोग भी उपस्थित थे।
- लोगों ने इस घटना के बाद भी रेबिज़ के उपचार हेतु कोई भी टीकाकरण नहीं किया था और मिशन रीव की भूमिका वहीं से शुरु होती है। मिशन रीव के कार्यकर्ता लोगों से मिले और पूरी जानकारी लेकर तुरंत डॉक्टर और सीएमओ से मिल कर इस पर कार्यवाही करवाने के लिए प्रयास किए।
- मिशन रीव के कार्यकर्ता बेल्ली, काकला और टिक्कर आदि गांवों में गए तथा लोगों से संपर्क किया जिन्हें इस ख़तरे का पता ही नहीं था।
- संबन्धित विभाग को सूचित करने के अलावा मिशन रीव ने वहां लोगों को जागरुता अभियान भी चलाया।
- डॉक्टर की टीम का सहयोग करते हुए समस्त प्रभावित लोगों को टीकाकरण किया गया जिसमें मिशन रीव ने अहम भूमिका निभाई।
- तीन माह के पश्चात् मिशन रीव के कार्यकर्ता दुबारा प्रभावित क्षेत्रों में गए तथा स्थिति का विश्लेषण किया। यह भी सुनिश्चित किया कि कोई इस प्रकार रेबिज़ की कोई घटना तो नहीं हुई।
- मिशन रीव का यह प्रयास प्रशासन द्वारा सराहा गया।

सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आवश्यकता आकलन प्रारुप

क्या आप आपकी किसी भी आपात स्थिति के लिए सभी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता महसूस होती हैं? Do you feel the need of all sorts of support in case of any emergency?	○ Yes	○ No
क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे के दौरान आपके परिवार के अलावा कोई और आपकी देखभाल भी करें? Do you desire that somebody else other than your family also takes care of you during old age?	○ Yes	○ No
क्या आप बीमा दावों के लिए किसी सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं? Do you feel the need of any assistance for insurance claims?	○ Yes	○ No
क्या आप अपने परिवार के लिए जीवन बीमा की आवश्यकता महसूस करते है? Do you feel the need of life insurance for your family?	○ Yes	○ No
क्या आपको अपनी संपत्ति/पशुधन/या किसी अन्य सामग्री/माल के लिए बीमा की आवश्यकता हैं? Do you require the insurance for your property/livestock/or any other material/goods?	○ Yes	○ No

लाइसेंस और यूटीलिटी डिविजन

प्रदेश के गांवों में लोगों के जीवन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिशन रीव के तहत बनाए गए 10 प्रभागों में से स्वास्थ्य प्रभाग एक है। करीब दो साल पूर्व जारी एक स्वास्थ्य रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल के बाद हिमाचल का दूसरा स्थान हैं। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते गांव में रहने वाले लोगों तक इन स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। इसी समस्या से निपटने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत गांव के लोंगों को घर – द्वार पर सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य प्रभाग बनाया गया। इस प्रभाग के तहत गांवों में लोगों को उनके घर तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहें हैं कि मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य प्रभाग कैसे काम करता है और कैसे आप इस प्रभाग का हिस्सा बनकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

ऐसे काम कर रहा मिशन रीव

प्रदेश सरकार की ओर से गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की अधिकतर योजनाओं का लाभ एक क्लिक पर लोग घर बैठे ले सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश के गांवों में आज भी लोगों को उन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है जो सरकार की ओर से विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाई गई है। इसी समस्या को दूर करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए आईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत लाइसेंस, यूटीलिटी और ऑनलाइन प्रभाग को तैयार किया गया है। इस प्रभाग के तहत लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें घर बैठे विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने में सहयोग किया जाता है। आईए जानते हैं कि मिशन रीव के इस प्रभाग के तहत कैसे लोगों के जीवन को आसान बनाया जा रहा है।

लाइसेंस निर्माण

आज के दौर में अगर आपको कोई भी कार्य शुरू करना हो, कोई वाहन खरीदना हो, अथवा कोई भी मशीनरी खरदनी हो तो इसके लिए आपके पास इसका अधिकार पत्र यानि लाइसेंस होना अनिवार्य है। तमाम तकनीकी सुविधाओं के बावजूद आज भी आम आदमी के लिए लाइसेंस बनाना किसी चुनौति से कम नहीं है। आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व अन्य कई तरह के दस्तावेजों को जुटाना एक लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने में आम आदमी को अपनी जेब ढीली करने के साथ-साथ कई सप्ताह लग जाते हैं। लोगों की इस समस्या को सुलझाने के लिए लाइसेंस, यूटीलिटी और ऑनलाइन सेवा डिविजन के तहत लोगों को बिना किसी परेशानी के मिशन

रीव सुलझाने में मदद करता है और सभी औपचारिकताएं बेहद कम समय में पूरी करने के साथ घर तक लाइसेंस बनाने में मदद करता है। जिसे व्यक्ति के पैसे और समय की बचत होती है। मिशन रीव के तहत लाइसेंस बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मिषन रीव के ऑनलाइन पॉर्टल पर सदस्यता लेनी होती है। इसके बाद प्रभाग का चयन कर अपनी आवश्यकता अनुसार आकलन कर फॉर्म भरना होता है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही ऑनलाइन जानकारी संबंधित क्षेत्र के मिशन रीव प्रतिनिधि के पास पहुंच जाती है और रीव प्रतिनिधि स्वंय इस व्यक्ति के पास पहुंच कर लाइसेंस बनाने की सभी औपचारिकताओं को पूरी करने में मदद करके लाइसेंस बनाकर घर तक पहुंचा देता है। अभी तक इस प्रक्रिया के माध्यम से तीन सौ से अधिक लोग लाइसेंस का निर्माण किया गया है।

यूटीलिटी सर्विसेज

पानी या बिजली का बिल जमा कराना हो, गैस कनेक्शन लेना हो, इंटरनेट लगाना हो, बिजली/पानी के लिए आवेदन करना हो या घरेलु जरूरतों से जुड़ी कोई अन्य सेवा लेनी हो तो यूटीलिटी सर्विसेज के तहत मिशन रीव तुरंत आपकी सेवाओं में उपस्थित है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवश्यकता आकलन फॉर्म भरना होगा और मिशन रीव प्रतिनिधि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपकी सेवा में हाजिर होगा। यह प्रतिनिधि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में सहयोग करेगा और आपकी आवश्यकता के मुताबिक आपका कार्य पूरा करेगा। इसके लिए आपका सरकारी कार्यालयों के अनावयश्क चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना होगा।

अन्य ऑनलाइन सेवाएं

आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेना है तो इस प्रभाग के तहत वह सभी सेवाएं आपको मिशन रीव की ओर से उपलब्ध कराई जाएगीं। उदाहरण के लिए बर्थ/डैथ सर्टीफिकेट, मैरिज सर्टीफिकेट, पासपोर्ट पंजीकरण, ऑनलाइन बिल भुगतान समेत तमाम तरह की सेवाएं

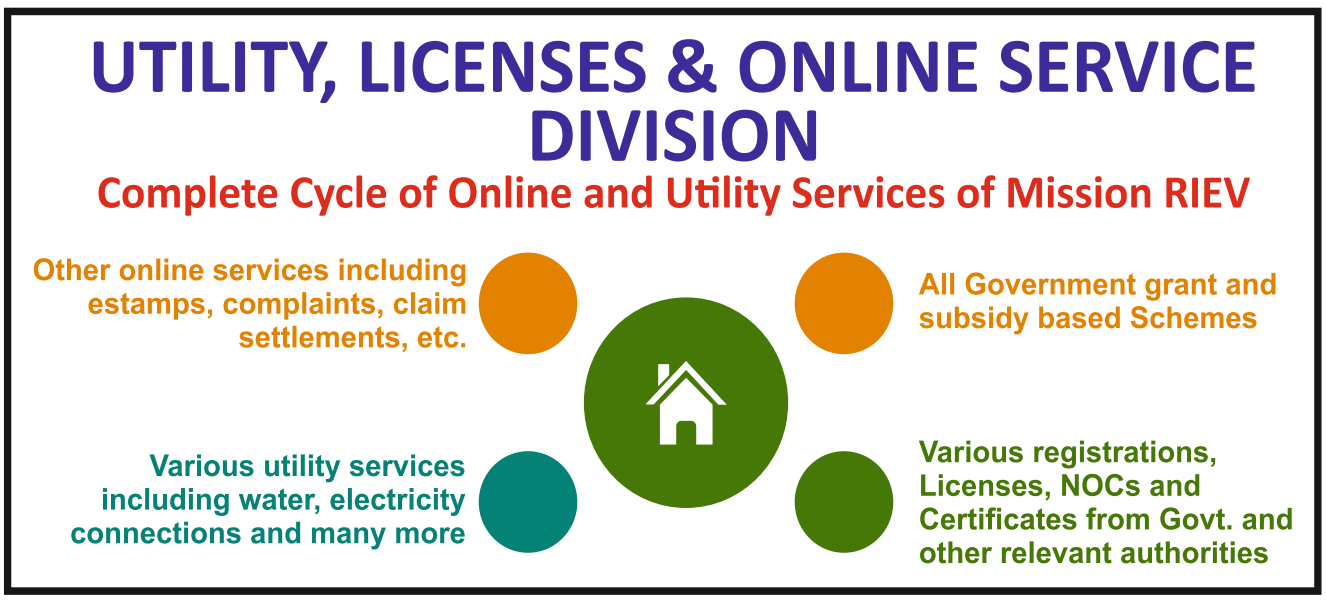

इस प्रभाग के तहत लोगों को उपलब्ध कराई जाती है।

ऐसे सहयोग करता है मिशन रीव

अगर आपको कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना है तो मिशन रीव प्रतिनिधि किस प्रकार आपकी सहायता करेगाए इसे समझने के लिए निम्न प्रक्रिया को समझें। मान लीजिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो इसके लिए प्रक्रिया यहां समझी जा सकती है-

पहला चरण

- जरूरी दस्तावेजों जैसे पंचायत प्रधान से प्रमाण पत्र/अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप
- ऑन लाइन ई डिस्ट्रिक वेबसाइट पर जाकर वहां पंजीकरण करना
- दी हुई आईडी के साथ लॉगइन करना
- एप्लीकेशन फार्म भरना और पेमेंट की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार हुई रसीद को डाउनलोड करना
- इस रसीद को नगर निगम/तहसील कार्यालय अथवा अन्य वांछित कार्यालय में जमा कराना
- इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद इसे पंचायत कार्यालय में भेजना ताकि नाम पंजीकरण हो सके।

सरकारी योजनाओं का लाभ

गांवो के लोगों को आज भी सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पाता है। यहां भी मिशन रीव सरकार और आम लोगों के बीच खाई को पाटने का काम करता है। मिशन रीव की ओर से समय-समय पर पंचायत में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है और उन्हें मिशन रीव के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। मिशन रीव के तहत सबसे पहले गांव के लोगों की आवश्यकता का आकलन किया जाता हैए उनकी जरूरतों को अच्छी तरह समझा जाता है और उसके बाद उन्हें उन योजनाओं की जानकारी दी जाती है जो उनके लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

अगर कोई व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसे योजना का लाभ उठाने की सभी औपचारिकताएं बताकर मिशन रीव प्रतिनिधी उन्हें पूरा करने में पूरा सहयोग देता है। इसमें अन्नापति प्रमाण से लेकर राजस्व रिकार्ड लेने समेत अन्य सभी तरह की दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें भी लाभार्थी को सरकारी कार्यालयों के अनावश्क चक्कर नहीं काटने पड़ते क्योंकि मिशन रीव सभी तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम है।

ई स्टेंप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य सेवाएं

अगर किस को ई स्टेंप की आवश्यकता है अथवा आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में कोई समस्या पेश आ रही है, तो यहां भी मिशन रीव आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। यानि आपकी ई मेल बनाने के छोटे कार्य से लेकर रिर्टन भरने, प्रमाण पत्र बनाने तक के सभी ऑनलाइन कार्य करने में मिशन रीव आपका सहयोग करता है।

सेवांओं की सूची

1	जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
2	मृत्यू पंजीकरण
3	जनजातीय प्रमाण पत्र
4	डोगरा क्लास प्रमाण पत्र
5	बोनफाइड/डोमेसाइल प्रमाण पत्र
6	ड्राइंविंग लाइसेंस पंजीकरण
7	प्रवासी मजदूर कांट्रेक्ट लाइसें
8	नया बिजली/पानी क्नेकशन
9	बीपीएल कार्ड पंजीकरण
10	पैन कार्ड पंजीकरण
11	पार्सपोर्ट पंजीकरण
12	वरिष्ठ नागरिक कार्ड
13	कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
14	डिजीटाइज्ड मैप, रिकार्ड के साथ
15	अनापत्ति प्रमाण पत्र
16	गैस कनेक्शन सुपोर्ट सर्विवेस
17	आय प्रमाण पत्र
18	सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं

आवश्यकता आकलन का प्रारूप नमूना

हमारा लक्ष्य लाइसेंस और यूटीलिटी डिविजन की गुणवत्ता को उत्कृष्ठता के साथ ऑनलाईन सेवाओं के माध्यम से सदस्य तक पहुंचाने की है । ऐसा कोई भी क्षेत्र जो लाइसेंस और यूटीलिटी डिविजन से संबन्धित हो उसे मिशन रीव के इस प्रभाग में शामिल किया गया है ।

क्या आप निम्नलिखित में से कोई पंजीकरण या प्रमाण प्त्र प्राप्त करने में सहायता चाहते हैं?
Do you want assistance in registration or to get any of the following certificates?

Birth, Deth, Marriage, Backward Area Certificate
Minority Class Certificate, Dogra Class
Income Certificate, Motor Transport worker Certificate
Shop Registration, Bonafide/Domicile Certificate

क्या आप को इनमें से किसी भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता हैं?
Do you need assistance in applying for any of these licences?

Driving licence (learner's/permanent) ☐
Migrant worker Contract licence ☐
Contract labour licence ☐
Renewal of Contract labour licence ☐

क्या आप को निम्नलिखित में से किसी के लिए आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता हैं?
Do you need assistance in applying for any of the following?

New Electricity connection/Reconnection ☐
BPL card ☐
PAN card ☐
Passport ☐
Senior citizen ID card ☐
Digitized map along with copy of rights record ☐
NOC from any department ☐
LPG Gas Connection ☐
Legal formalities in order to become heir/making will power of attorney/decree ☐

SUBMIT

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग

मिशन रीव गांव–गांव में किसानों के लिए एक अदद मार्केट तैयार कर रहा है ताकि किसानों के उत्पादों के उनके गांव में मार्केट भी मिल जाए और बेहतर दाम भी। वर्तमान में देखा जाए तो किसानों से आढ़ती या मध्यस्त बड़े ही कम दामों पर उनके उत्पाद खरीद लेते हैं तथा मार्केट में ले जाकर उनके दाम कई गुणा बढ़ाकर लोगों को बेचे जाते हैं। किसानों को लाभ नाममात्र का ही होता है क्योंकि किसानों को मार्केटिंग का ज्ञान ही नहीं है। मिशन रीव अपने इसी प्रभाग में किसानों के लिए उचित दाम और घर पर ही मार्केट की सुविधा देने के प्रयास में सेवारत है।

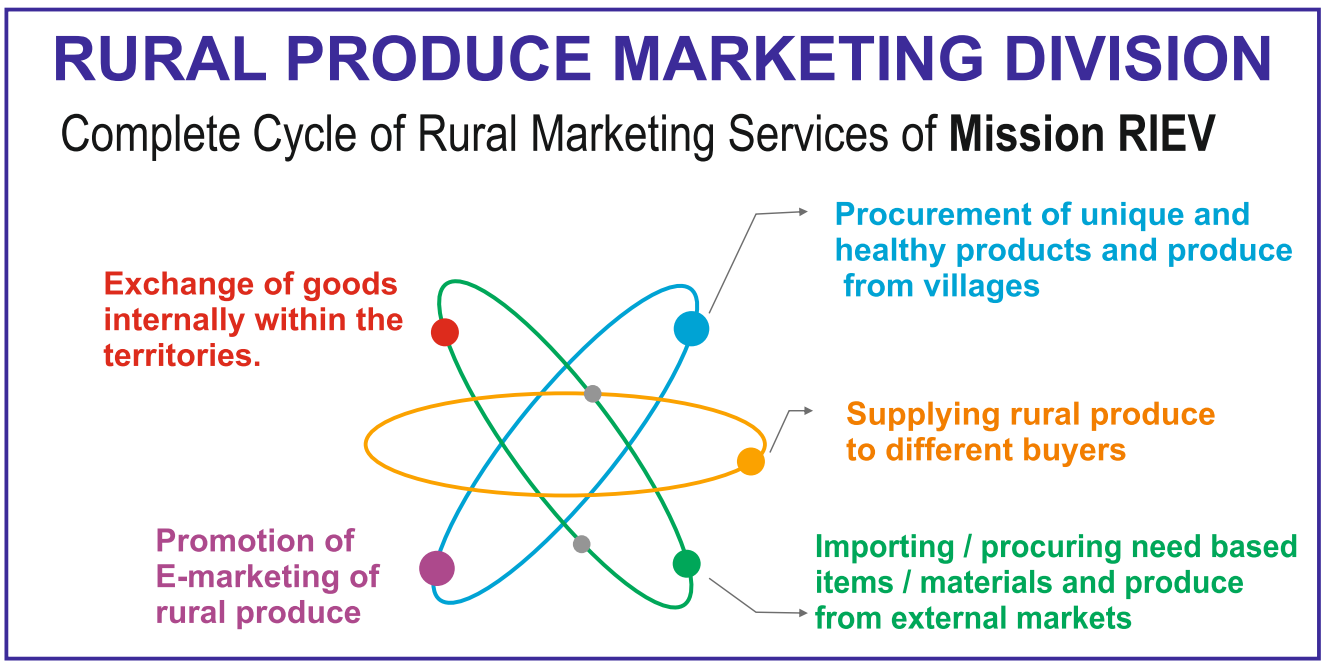

ग्रामीण मार्केट ही क्यों

- विश्व के दो-तिहाइ देश की आबादी कृषि पर निर्भर है तथा उनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर ही आधारित है।
- भारत की 70 प्रतिशत से अधिक की आबादी कृषि पर ही निर्भर है।
- भारतीय जीडीपी का आधार ही कृषि है।
- मध्यस्तता करने वाले आढ़तियों का शोषण किसानों पर लगातार होता है।
- किसानों को अनुदान आधारित योजनाओं की जानकारी का अभाव।

क्या कर रहा है मिशन रीव

- किसानों के लिए क्रय/विक्रय के बहुतायत में विकल्पों को प्रस्तुत करेगा मिशन रीव
- सर्वश्रेष्ठ डील यानि जहां किसानों को अधिक लाभ होगा उसमें सहायता करेगा।
- सरकारी विक्रेताओं/वितरकों से सीधा संपर्क करवाने में सहयोग
- रसद/लॉजिस्टिक हेतु सहयोग करना
- किसानों को उनके उत्पादों की प्रदर्शनी हेतु स्थान उपलब्ध करवाने में सहयोग
- कमीशन एजेंट आदि रुकावटों को किसानों से दूर करना
- पारदर्शी मार्केट की उपलब्धता की सुनिश्चितता बनाना जहां किसान सीधा लाभ ले सके।
- रसद एवं गोदामों की व्यवस्था करना भी मिशन रीव की प्राथमिकता है।

इस प्रभाग में मिशन रीव की सेवा प्रक्रिया

- सदस्यता
- आवश्यकता आकलन

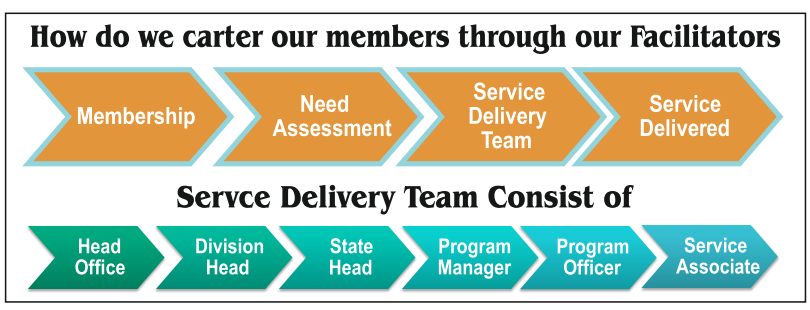

- सेवा वितरण टीम
- सेवा वितरण

सेवा वितरण टीम का प्रारूप

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग के अंतर्गत सेवाऐं

- उत्पादों के उत्पादन में सहयोग
- उत्पादों के क्रय-विक्रय में सहयोग
- समग्र प्रचालन/ऑपरेषनल सहयोग
- रसद/लॉजिस्टिक सहयोग
- फसलों के संरक्षण एवं गोदाम में रख-रखाव में सहयोग

उत्पादन सहयोग

मिशन रीव ग्रामीण लोगों एवं किसानों के साथ ही उनके उत्पादों को और अधिक मज़बूत करने के प्रति दृढ़ता विश्वास करता है। हम यह भी विश्वास करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि किसानों को नई कृषि तकनीकों से लैस किया जाए तथा सरकार की इस क्षेत्र में संचालित कृषि योजनाओं एवं अनुदान आदि की संपूर्ण जानकारी किसानों को समय पर मिले।

इसके दो भाग हैं

सर्विस एसोसियेट

1. मिशन रीव द्वारा निर्धारित फॉर्म को आवश्यकता आकलन के आधार पर भरना
2. सदस्यों को उनके उत्पादन आदि से संबन्धित परामर्श उपलब्ध करवाना।

कार्यक्रम अधिकारी

1. सदस्यों की आवश्यकता आधारित उपकरणों एवं अन्य समस्त सहायता हेतु उचित एंव आवश्यक प्रबंध करना
2. सदस्यों को समस्त वांछित कृषि उपकरणों आदि को उपलब्ध करवा कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना

क्रय–विक्रय सहयोग

सदस्यों की आवश्यकता के आधार पर उत्पादों को क्रय-विक्रय के लिए योजना बनाना जिसके लिए आवश्यक है :

1. योजना
2. मानकों की पहचान
3. क्रेता और विक्रेता की खोज एवं उनकी पहचान
4. गुणवत्ता मुल्यांकन
5. कीमतों का मोल-भाव
6. समुचित वितरण व्यवस्था

इसके दो भाग हैं

सर्विस एसोसियेट

1. आवश्यकता आकलन आधारित निर्धारित फॉर्म को भरना तथा जिस उत्पाद को बेचना और खरीदना है उसकी जानकारी लेना

कार्यक्रम अधिकारी

1. श्रेष्ठ मार्केट का चयन करना जहां किसानों को उनके उत्पाद को बेचने या खरीदने के लिए सही स्थान मिले और उसके सही दाम भी प्राप्त हो सके।

समग्र प्रचालन / ऑपरेशनल सहयोग

सदस्यों को बेहतर ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट एवं बेहतर सुविधा को उपलब्ध करवाना जिसमें उनके उत्पाद क्रय अथवा विक्रय हेतु उनको आसनी हो।

इसके दो भाग हैं

सर्विस एसोसियेट

1. इसके मिशन रीव का निर्धारित फॉर्म को भरना तथा सदस्यों की आवश्यकता को जानना।
2. सदस्यों को उनके उत्पादन आदि से संबन्धित परामर्श उपलब्ध करवाना।

कार्यक्रम अधिकारी

1. सदस्यों की आवश्यकता अनुसार उनको उपकरणों एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता करवाने में सहयोग प्रदान करना।
2. सदस्यों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना, आपूर्ति आदि के बाद प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. मार्केट का चयन करके सदस्यों को सुविधा प्रदान करना।

रसद/लॉजिस्टिक सहयोग

इसमें संपूर्ण प्रबंधन आता है जिसके तहत साधन/संसाधन को कैसे, कहां से उपलब्ध करवाना है तथा सदस्यों तक किस प्रकार पहुंचाकर उनको सेवा देनी है।

गोदाम और फसलों के संरक्षण में सहयोग

गोदाम से यहां अभिप्राय उत्पादों को रखने का सुरक्षित स्थान से है। गोदाम का उपयोग उत्पादकों, आयातकों, निर्यातकों, थोक व्यापारी, परिवहन व्यवसाय, कस्टम आदि द्वारा किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में अधिकतर आबादी कृषि आधारित है इसलिए गोदामों की आवश्यकता भी अधिक है।

सर्विस एसोसियेट

1. मिशन रीव द्वारा निर्धारित फॉर्म भरने के बाद इसे सुनिश्चित करना होता है कि सदस्य यदि गोदाम बनाना चाहता है अथवा उसे गोदाम की आवश्यकता है तो उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम अधिकारी

1. सदस्य की आवश्यकतानुसार गोदाम की व्यवस्था करना
2. गोदाम के निर्माण के लिए आवश्यक प्रबंध करना

कार्यक्रम प्रबंधक

निर्माण के दौरान समस्त पहलुओं की जांच एवं देख-रेख करना

आवश्यकता आकलन का प्रारूप नमूना

क्या आप अपने घरेलू स्तर पर फसलों/हस्तकला/ कलाकृतियों / विदेशी फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं? Do you want to produce crops/ handicraft/ artifacts / exotic crops at your home level?	○ Yes ○ No
क्या आप सर्वोत्तम मूल्य पर फसलों / हस्तकला / कलाकृतियों / विदेशी फसलों को खरीदने या बेचने के लिए समर्थन चाहते हैं? Do you want support to buy or sell crops/ handicraft/ artifacts/ exotic crops at best price?	○ Yes ○ No
क्या आप खरीद, उत्पादन, फसलों के विपणन/हस्तकला/ कलाकृतियों/ विदेशी फसलों सहित समर्थन का अंत चाहते हैं? Do you want the end support including procurement, production, marketing of crops/ handicraft/ artifacts/ exotic crops?	○ Yes ○ No
क्या आप लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहते हैं? Do you want logistics support?	○ Yes ○ No
क्या आपको वेयरहाउसिंग का समर्थन चाहिए? Do you want warehousing support?	○ Yes ○ No

SUBMIT

An Innovative Step Towards Bringing Smiles

It is said that our knowledge, consciousness and resources are owned by God and us humans are merely their users and carer takers. These gifts have been bestowed to us for sharing with the needy people around us, and not to merely hoard them. More we try to distribute them, God blesses us with more resources and if we try to accumulate more for ourselves, there will always remain the fear of their speedy depletion.

The effect of all our thoughts, resolutions, and actions revolves in the universe and begins to come back to us with a qualitative volume; this is the law of the universe. If we generate positive, optimistic and constructive views, then we find ourselves more useful in the journey of life. If the money earned by our hard work is used to reduce the sufferings of people in contact with us, nature initiates the process of creating wealth for us in manifolds. But if we put out sadness, anxiety, fear, greed and jealousy, then the corresponding impact will come back to us in greater amounts. We get the multiple level of happiness by creating smiles on others faces through sharing the sorrows and creating hopes in the lives of others. Lack of knowledge of this cosmic law is also one of the reasons for most of the human sufferings. If this law is imbibed, the society can become peaceful with prosperity all around. Perhaps this is what we all imagine a rich and prosperous society is like. Happiness is more a matter of mind than wealth because even a poor person can feel cheerful as compared to a wealthy king. Mental prosperity leads to economic prosperity, whereas financial prosperity can never provide mental prosperity. Now the question is what initiative can be taken to bring mental prosperity combined with a smile on the faces of people, instead of a pain-laden visage.

For this, it becomes necessary to discuss human concerns. In today's world where everyone is busy and, in a race, to get ahead in earning money, the symptoms, types and volumes of the concerns of the people struggling to meet basic needs are different in many ways. Therefore, it becomes imperative to find root causes of the concerns otherwise, the worries will remain as they are.

Concerns vary according to the age gap and begin to shape themselves according to different occupations. Whereas these concerns arise due to non-fulfilment or untimely fulfilment of basic needs in the desired way. Many times, our inability to differentiate between needs and desires also causes anxiety. In such a situation, the requirements of people remain more or less identical in the age segments of 0-6; 7-12; 13-19; 20-25; 26-35; 36-50; 51-60; 61-70; and 70 above.

Apart from this, efforts can also be made to address the needs and concerns of people in the sectors of education, health, agriculture, business management, social security, rural product marketing, financial and banking cooperation, benefits from various government schemes and various online services, etc.

When an effort is made to support people in resolving their problems and issues in holistic manner in such a wide range, it imperatively creates need of functionaries in large numbers for the execution of this vital exercise, in which the inclusion of honorarium, working mechanism, technological support, system, etc. are going to be essential requirements.

Eventually, a kind of business model starts to form and arrangements like consumer charges become a necessary component to meet all the expenses. When we combine services with money, then those services do not remain an exercise done for someone's welfare and there is a possibility of the loss of quality of services if offered free of charge.

In such a situation, it becomes challenging to establish this idea of social responsibility without excellence in services, quality in performance and seeing a big smile on the faces of people whereas it may become a cause of anxiety if some charges are taken to ensure qualitative operation at all levels. This dilemma paves the way to write a new chapter to leave it to the good sense of the users or beneficiaries to pay whatever they deem appropriate, while the service providers make every effort to deliver each service wholeheartedly.

The successful completion of Mission RIEV's 2 years and the lessons learnt during this period gives us immense pleasure to present RIEV's updated version before the people of Himachal and other under expansion phase with the ideal message of "Dil Se Sewa – Dil Se Bhugtan".

It makes us profoundly optimistic and happy to further the implementation of this project which is experimental yet true to its mission of bringing a smile on every face.

Dr. LC Shrma
Editor-in-Chief
md@iirdshimla.org

Rural Consumerism

India's economic growth has accelerated swiftly in the last two decades and so has the purchasing power of its population. McKinsey Global Institute (MGI) study suggests that if India continues to grow at the current pace, average household incomes will triple over the next two decades, making the country the world's fifth-largest consumer economy by 2025. The growing income and rising influence of the social media has enabled consumers to binge on good things irrespective of their prices.

India's rural population, accounting for about 12 per cent of the world's population, presents a huge, untapped market. Brands cannot afford to disregard vast opportunities rural India offers, taking into consideration the population density in such areas. Almost 67 per cent of companies in India are expanding their presence in tier IV cities.

A stronger rural India with increasing consumerism is also inciting demand for products and services. The people in the rural areas are now quality conscious and thus the rural market is emerging fast lucrative. Also, the increase in rate of literacy in rural areas has led to employment opportunities and hence higher incomes. The retail sector in these remote areas are becoming more organized and has become the second major occupation after agriculture.

A blend of consistent agro commodity prices, better irrigation facilities and greater involvement by the government in the agriculture sector has resulted in an increase in income of the farmers of rural India. Increased government involvement and better infrastructure has resulted in a meaningful impact on farmer's income and thus rural consumption demand.

Another reason for increase in rate of consumption in rural India is the exposure of internet and social media. The rural population has got exposed to the standard of living of the urban population and has started expecting a similar lifestyle for themselves. The masses demand better quality products and money worthy services. Big companies are increasingly sculpting their strategies and brand marketing to influence consumer in rural areas. Hindustan Unilever aimed to empower rural women to make its products reach every rural home by training rural women, reportedly, this initiative now delivers around 20 per cent of Unilever's overall rural sales. Meanwhile Godrej Consumer Products trains rural youth in channel sales. ITC has Choupal Sagar and Godrej Agrovet has large format retail stores called Adhaar in Indian hinterlands, While Coca-Cola, the beverage major since it re-entered India, intends to increase its rural reach.

Today, in spite of comparatively low incomes, rural consumers due to their majority share of the population altogether are India's largest consumers — 57% of current consumption is in rural areas versus 43 percent in cities. However, it is assumed that by 2025 the Indian consumer market will largely be an urban affair, with 62 percent of consumption in urban areas versus 38 percent in rural areas.

Most of the companies are steadily transforming their rural operations into viable profit centres. They have been devising 'reach strategies' which proved to be instrumental in selling to unsophisticated buyers in geographically dispersed locations.

According to Tata Strategic Management Group report, about one-third of fast-moving consumer goods (FMCG) and consumer durables are sold in rural markets. Companies that recognize this enormous opportunity are experimenting with various go-to-market models to garner their share of this growth. But the results have been mixed. An efficient sales and distribution model are the most critical factor to achieve profitable and sustainable growth in rural markets.

The hallmark of success in rural India is overcoming challenges in the three stages of the consumer lifecycle reaching, acquiring and retaining the rural customer. In terms of reaching the rural consumer, the biggest obstacles companies facing are inadequate distribution networks, partners with limited capabilities, long payment cycles, and weak marketing channels. As far as rural customer acquisition is concerned, understanding and meeting the diverse, specialized needs and preferences of such customers pose major challenges to companies.

As rural markets evolve and competition in rural markets intensifies, companies will have to look for new approaches to harness this opportunity in ways that protect their margins while also growing revenue. Deploying the correct sales and distribution model can assist companies in driving profitable growth in a relatively short span of time. Rural masters will have to find ways to scale operations without hurting their bottom line. For a rural performer, the challenge will be to create differentiated offerings and brand loyalty to retain customers and sustain their business models. Rural voyagers will build their own ecosystems and brand awareness to acquire new customers.

Mission RIEV, provides everything that companies require - consumer reach, acquisition and retention along with strong distribution networks of more than 10,000 dedicated people across Himachal Pradesh and on the success of this pilot project, it aims to go PAN India with the model. Through its reach and strong connect with family members in the village it has been able to increase the capabilities, reduce long payment cycles and enhance the marketing channels. With its vast & active network, Mission RIEV understands diverse local markets and consumer needs.

Mission RIEV provides immense opportunities for all big companies and multinationals for selling their products in geographically dispersed locations. An enormous opportunity waits these companies to experiment and garner market share and increase their growth and make their operations into a viable profit centre.

Join us in our initiative of making products available by reaching the last person in the village!

Anand Nair
Guest Writer
anand@iirdshimla.org

उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग

युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। अगर कोई युवा अपना व्यवसाय शुरु करना चाहता है तो उसे आर्थिक सहायता से लेकर कौशल प्रशिक्षण तक की व्यवस्था है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब उद्यमी के तौर पर व्यवसाय तो व्यक्ति शुरु कर देता है लेकिन सही मार्गदर्शन और व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए तकनीकी सहायता उसे नहीं मिल पाती। यही कारण है कि छोटे उद्यमी अक्सर व्यवसाय शुरु करने के एक साल के भीतर ही हिम्मत हार जाते हैं और कोई जोखिम उठा कर व्यवसाय को आगे ले जाने की जगह उसे बंद करना ही बेहतर समझते हैं। इसी समस्या से पार पाने के लिए मिशन रीव की ओर से विकास मॉडल के तहत बनाए गए दस प्रभागों में उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग को विशेष तौर पर शामिल किया गया है।

"मिशन रीव ने उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने और प्रशिक्षण से लेकर लोन सुविधा तक सराहनीय पहल की है।

उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास यानि ईबीडी के अंतर्गत मिशन रीव उद्यमिता सहयोग सेवाएं यानि ईएसएस देने में प्रयासरत है जिसमें कई युवाओं को लोन व अन्य सुविधा प्रदान की जा चुकी है तथा यह प्रयास निरंतर जारी है। युवाओं को बेरोजगार होने की स्थिति में अपना कोई भी व्यवसाय शुरु करने के लिए मिशन रीव से जुड़कर उसकी समस्त औपचारिकताओं से मुक्ति देकर रीव व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण एवं लोन आदि की सुविधा प्रदान कर व्यवसाय को स्थायित्व देने में सहयोग कर रहा है।"

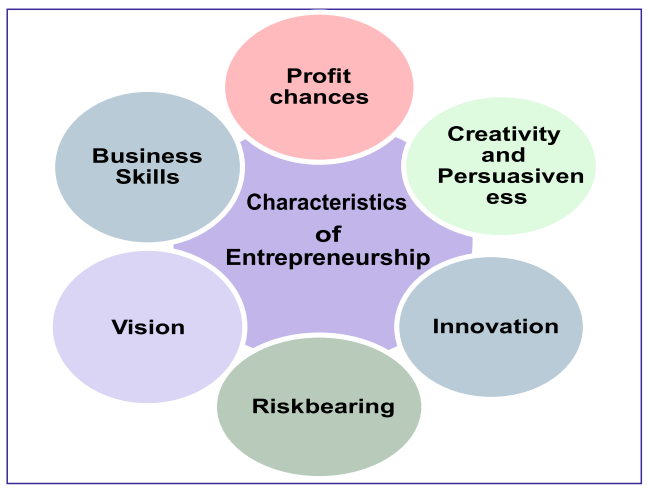

उद्यमिता के संदर्भ में मिशन रीव

मिशन रीव को सदस्यों की आवश्यतानुसार इस प्रभाग में नव उद्यमियों के लिए विशेष सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन करने का प्रावधान है। मिशन रीव कैसे नया व्यवसाय शुरू करने में अथवा पहले से स्थापित व्यवसाय को आगे ले जाने में आपकी सहायता करता है, इस प्रक्रिया को आप यहां समझ सकते हैं:

ऐसे सहयोग करता है मिशन रीव

- लघु उद्योग एवं व्यवसाय के लिए विश्लेषणात्मक वातावरण तैयार करना
- उत्पादों अथवा सेवा के चयन में सहयोग करना तथा उसके लिए प्रस्ताव तैयार करना
- लघु उद्योगों की स्थापना के लिए समस्त औपचारिकताओं और आवश्यक जानकारियों को प्राप्त करना
- लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिए प्रबंधकीय कौशल की व्यवस्था करना

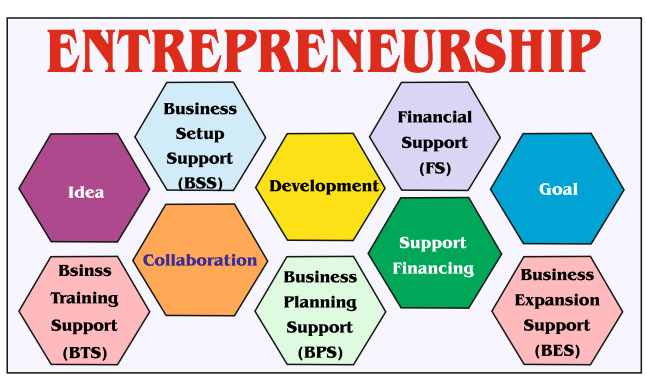

विशेष सेवाएं

- व्यवसाय योजना की पहचान करना
- वित्तिय एवं तकनीकि संस्थानों से संपर्क करवाना
- समस्त सरकारी लाईसेंस, स्वीकृति पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र
- व्यवसायिक एवं वित्तिय योजना निर्माण
- तकनीकि सहयोग एवं प्रशिक्षण

आवश्यकता आकलन

किसी भी व्यक्ति की सहायता करने से पूर्व मिशन रीव के तहत सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। इस आकलन के बाद आवश्यकता के अनुसार उद्यमी बनने वाले इच्छुक व्यक्ति की सहायता की जाती है।

बैंकिंग एवं वित्तिय खंड के अंतर्गत सेवाएं

- व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु सहयोग
- व्यवसाय स्थापन हेतु सहयोग
- वित्तीय सहयोग
- व्यवसाय योजना सहयोग
- व्यवसाय को बढ़ाने हेतु सहयोग
- सूचना तकनीकी सहयोग

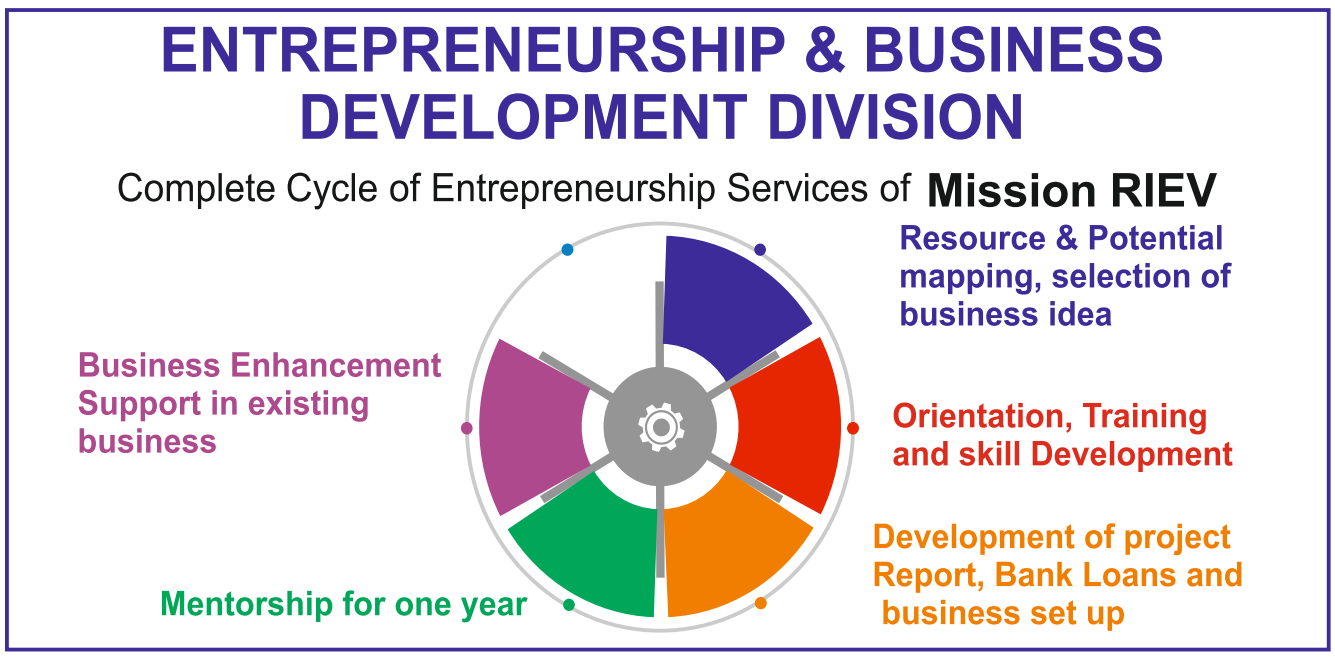

उद्यमिता क्षेत्र में मिशन रीव की उपलब्धियां

फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विकास खण्ड जुब्बल - कोटखाई में **बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस प्रभाग** के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को स्थापित कर रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय पहल की है। गौरव शर्मा जो कि जुब्बल से संबन्धित है, द्वारा मिशन रीव में आवश्यकता आकलन के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया गया।

इसके लिए मिशन रीव ने समस्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना पर कार्य किया तथा फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को स्थापित किया। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत 10 लाख 40 हज़ार रुपये थी जिसके लिए मिशन रीव द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युको बैंक जुब्बल से लिंक करवाकर गौरव शर्मा को यह लोन स्वीकृत करवाया गया।

लोन लेने के बाद मिशन रीव ने ही मशीन और उसके उपकरणों को पहचान कर स्थापन में भी सहयोग किया। इस प्रोजेक्ट को बनाने, लगाने तथा क्रियान्वयन में मिशन रीव ने संपूर्ण सहयोग किया। गौरव शर्मा ने द रीव टाइम्स को बताया कि मिशन रीव को आवश्यकता आकलन में रोजगार के लिए आवेदन किया था तथा इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को लगाने पर चर्चा के बाद उसके स्थापन के लिए मिशन रीव ने इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाया है।

इस प्रोजेक्ट की पूरी रुपरेखा और क्रियान्वयन मिशन रीव के तहत हुआ तथा इसकी स्थापना के बाद न केवल मुझे अपने घर पर ही सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि मेरे साथ कई बेरोजगारों को भी रोजगार मिला है। मैं मिशन रीव का बहुत आभारी हूं क्योंकि मुझे इस मशीन और व्यवसाय की जानकारी नहीं थी।

ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़

राजगढ़ सिरमौर से प्रीतम ठाकुर ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने मिशन रीव के तहत आवश्यकता आकलन में ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़ के लिए आवेदन किया था।

मिशन रीव ने इस आवश्यकता को समयसीमा के तहत ही पूरा करते हुए राजगढ़ में टीम के सहयोग से इसकी पूरी रुपरेखा तैयार कर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यह अनुमानित रुप से 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट था। संबन्धित बैंक से लिंक कर यह लोन स्वीकृत करवाया गया तथा उसके बाद ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़ को स्थापित कर उद्यमिता के लिए बेहतर शुरुआत की गई। प्रीतम ठाकुर ने बताया कि मुझे ऑटामोबाइल में प्रशिक्षित होने के बाद भी रोजगार के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था। न ही मुझे औपचारिकताओं का पता था। ऐसे में मिशन रीव ने मेरा मार्गदर्शन किया तथा प्रोजेक्ट बनाकर, लोन स्वीकृत करवाकर स्थापित कर दिया। मेरे साथ इसमें कई और बेरोजगारों को मैं अब रोजगार दे रहा हूं। मिशन रीव को इसके लिए आभार जताया।

गारमेंटस् सेल शॉप

ऐसा ही उद्यमिता का सफल उदाहरण देहरा गोपीपुर, कांगड़ा की प्रियंका कुमारी का है जिसको मिशन रीव सहारा बना है। प्रियंका गारमेंटस् सेल शॉप के माध्यम से व्यवसाय करना चाहती थी। इसके लिए मिशन रीव ने प्रोजेक्ट तैयार कर समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया तथा बैंक से 9 लाख अस्सी हज़ार का लोन दिलवाने में रीव ने ही सहयोग किया। आज प्रियंका गारमेंटस् सेल शॉप के माध्यम से अपने रोजगार में बढ़ौतरी करते हुए एक सफल उद्यमी बनने की राह पर है। प्रियंका कुमारी ने द रीव टाइम्स को बताया कि मिशन रीव के माध्यम से उनके उद्यम को राह मिली और उनके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सका। आज मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूं।

इसके अलावा भी उद्यमिता क्षेत्र में मिशन रीव प्रत्येक श्रेणी मे निरन्तर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे लघु, मध्यम, सिमान्त उद्योगों के व्यवस्थापन एवं अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूरा करके आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत है।

आवश्यकता आकलन का प्रारुप

क्या आप एक नया व्यापार उद्यम शुरू करना चाहते हैं? Do you want to start a new business venture?	NEW BUSINESS SUPPORT	○ Yes ○ No
क्या आपके पास अपना खुद का व्यवसाय है और इसे एक अधिक सफल उद्यम बनाने के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता हैं? Do you have business of your own and need our support to make it a more successful venture?	EXISTING BUSINESS SUPPORT	○ Yes ○ No
क्या आपके अपने व्यवसाय के लिए आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) का समर्थन करना चाहते हैं जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लिकेशन अनुपात/सॉफ्टवेयर विकास आदि ? Do you want IT (Information Technology) support like website designing, Application/ software development, etc for your business?	TECHNOLOGY SUPPORT	○ Yes ○ No

भूमि तथा संपत्ति प्रबंधन

संपत्ति प्रबंधन किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। बात निजी संपत्ति हो सरकारी संपत्ति की हो अथवा व्यवसायिक संपत्ति की, प्रबंधन की आवश्कता रहती है। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं अथवा किसी भी तरह का कोई निर्माण या जमीन की बिक्री अथवा खरीद करना चाहते तो आपको इसके लिए विशेष तरह के प्रबंधन की आवश्कता रहती है। जमीन की डिमार्केशन, राजस्व विभाग से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य औपचारिकताएं आदि कुछ ऐसी प्रकियाएं जिनमें व्यक्ति की अच्छी खासी कमाई खर्च हो जाती है और कई महीनें इन दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने में लग जाते हैं। जबकि मिशन रीव के तहत संपत्ति प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य सभी कार्य तय समय में बेहद कम खर्च पर व्यक्ति को उसके घर पर करके दिए जाते हैं। इस प्रभाग के तहत विभिन्न चरणों में संपत्ति प्रबंध में लोगों का सहयोग किया जाता है।

संपत्ति प्रबंधन में मिशन रीव

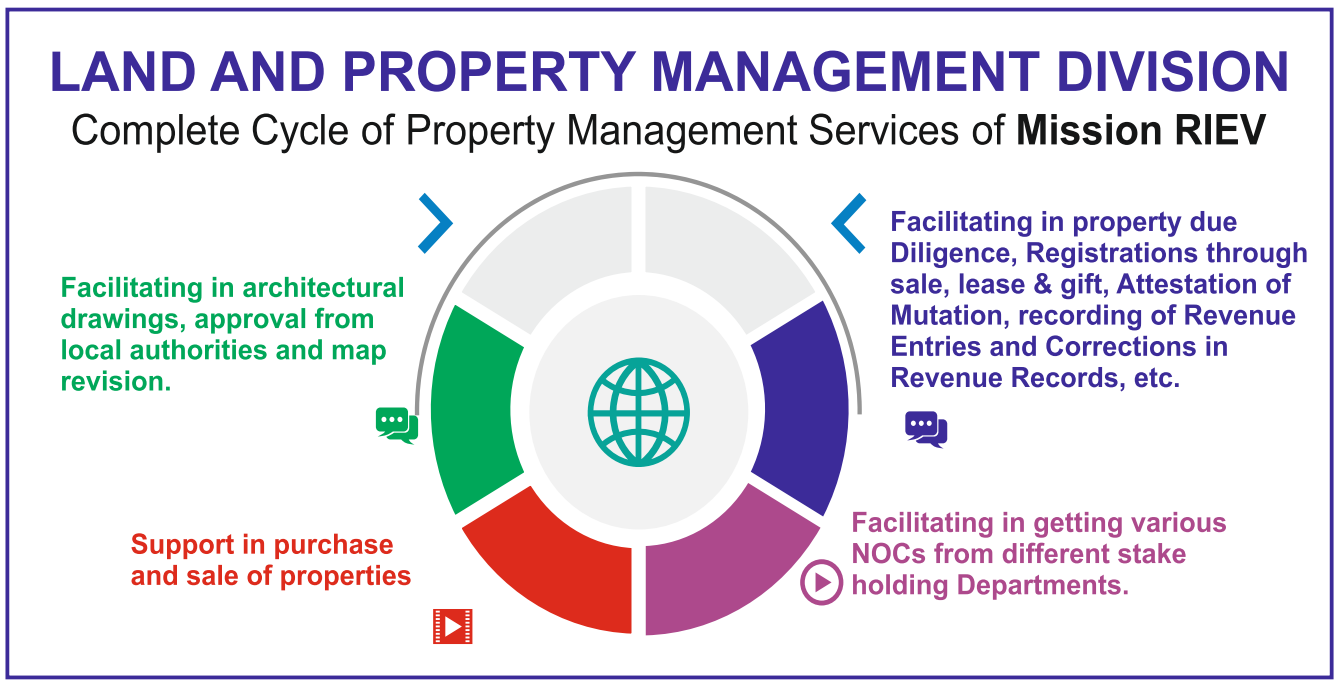

अपना घर/संपत्ति खरीदते समय अपना समय, पैसा और संसाधनों का निवेश करते हैं। एक निवेश के रूप में संपत्ति खरीदने के बाद अथवा व्यवसाय से अर्जित संपत्ति के प्रबंधन के बारे में बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। लेकिन अकेले संपत्ति का प्रबंधन करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। संपत्ति का प्रबंधन करने के दो तरीके हैं - एक स्व-प्रबंधन है और दूसरा एक अच्छे संपत्ति प्रबंधक की व्यवस्था करना जो आपके लिए काम करेगा। मिशन रीव यहां आपके दोनों विकल्प को पूरा करता है। हर व्यक्ति/व्यवसायी अथवा संपत्ति अर्जित करने वाले को संपत्ति प्रबंधन के लिए किसी न किसी चरण पर संपत्ति प्रबंधक की आवश्यकता है। मिशन रीव वास्तव में दोनों हो स्थितियों में आपके सहयोगी के तौर पर काम करता है। स्वप्रबंधन में एक सलाहकार और प्रबंधक के तौर पर सारी संपत्ति का प्रबंधन करने का विकल्प मिशन रीव अपने सहयोगियों को देता है।

बतौर संपत्ति प्रबंधक

मिशन रीव संपत्ति के क्रय अथवा विक्रय के संबंध में निर्णय लेने से पहले लागत और लाभ का वजन और पेशेवरों और विपक्षों का अध्ययन करने में मदद करता है अथवा अपने स्तर पर यह कार्य करता है। मिशन रीव के संपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि बतौर संपत्ति प्रबंधक अचल व चल संपत्ति उद्योग के सभी पहलुओं में अत्यधिक कुशल हैं। वे अच्छी तरह से बाजार को समझते हैं। वे बाजार की स्थितियों के मुताबिक आपकी संपत्ति पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

संपत्ति प्रभाग के तहत सेवाएं

राजस्व विभाग से जुड़ा कोई भी कार्य हो, व्यक्ति को इसके लिए समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। राज्य विभाग में किसी भी कार्य के लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया काफी थकाऊ होती है। ऐसे में मिशन रीव एक सच्चे सहयोगी की तरह आपका साथ देता है। राजस्व विभाग संबंधित से कोई भी कार्य हो उन्हें पूरा करने में मिशन रीव की ओर से भरपूर सहयोग दिया जाता है।

डिमार्केशन

अगर कोई व्यक्ति जमीन की डिमार्केशन करवाना चाहता है तो उसके लिए जो भी औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करने में मिशन रीव की ओर से सहयोग किया जाता है। जैसे संबंधित क्षेत्र के पटवारी को साइट तक लाना, इसके लिए जरूरी कागजात एकत्र करना और तहसीलदार को एप्लीकेशन, जमाबंदी, खसरा नंबर आदि इन सभी दस्तावेजों को तैयार करने में मिशन रीव की ओर से पूरा सहयोग किया जाता है।

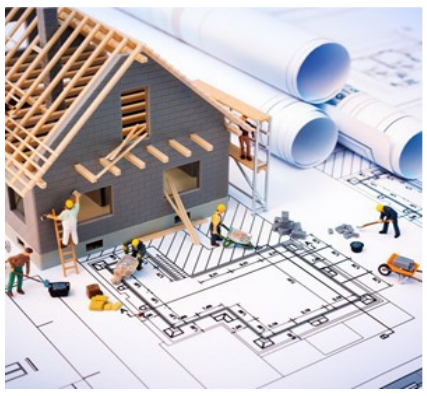

राजस्व कोर्ट केस

राजस्व से संबंधित किसी भी तरह के मामलों के निपटान में मिशन रीव की ओर से लोगों का सहयोग किया जाता है।

प्लॉट कटिंग

अगर किसी की साझी जमीन है और वह इसका बटवारा करना चाहता है अथवा कोई एक व्यक्ति जमीन के किसी बड़े टुकड़ों का प्लॉट विभाजन करना चाहता है तो यहां भी मिशन रीव की सेवाएं उपलब्ध हैं।

राजस्व प्रमाण पत्र

अगर आप राजस्व विभाग से किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो मिशन रीव ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीकों से मददगार है।

नक्शा तैयार / मंजूर करना

किसी भी तरह के भवन निर्माण के निए नक्शा तैयार करना हो, नाप नपाई करनी हो अथवा संबंधित विभाग से नक्श मंजूर करना हो। इन सभी प्रक्रियाओं को मिशन रीव द्वारा पूरा किया जाता हैं। यहां तक कि नक्शा बनाने के लिए किफायती दाम पर वास्तुकार का प्रबंध करने में भी मिशन रीव सहयोग करता है साथ ही साथ नक्शे में समय और जरूरत के हिसाब से संशोधन में भी मिशन रीव आपका सहयोगी है।

जमीन की खरीद / बिक्री

अगर कोई जमीन की बिक्री करना चाहता है अथवा जमीन खरीदने का इच्छुक है तो उसका प्रबंध भी मिशन रीव की ओर से किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जमीन की बिक्री करना चाहता है और उसके लिए उसे सही खरीददार नहीं मिल रहा तो खरीददार ढूंढने से लेकर जमीन की रजिस्ट्री करवाने तक में मिशन रीव सहयोग करता है। इसके अलावा जमीन खरीदने में भी दस्तावेज तैयार करने से लेकर पूरी प्रक्रिया में मिशन रीव योगदान देता है।

ऐसे काम कर रहा मिशन रीव

जमीन से जुड़े किसी भी कार्य को करने के लिए मिशन रीव किस तरह आपकी मदद करता है इस प्रक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है। अगर आप को जमीन की डिर्माकेशन करानी है तो सबसे पहले आपको आवश्यकता आकलन में संपत्ति प्रभाग में जाकर लैंड डिर्माकेशन पर क्लिक कर फार्म भरना होगा।

इसके बाद मिशन रीव प्रतिनिधी आपको लैंड डिर्माकेशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देगा और डिर्माकेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची तैयार करेगा। सूची तैयार करने के बाद रीव प्रतिनिधि जरूरी कागज जैसे जमाबंदी, बंदोबस्ती नक्शा, ततीमा, खसरा नंबर इत्यादी का प्रबंध कर पूरे कागज तैयार करेगा।

उसके बाद वह स्वंय संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के कार्यालय जाएगा और आपको अनावश्यक रूप से तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मिशन प्रतिनिधि ही डिर्माकेशन से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में सहयोग करता है। इसी तरह संपत्ति प्रबंधन से जुड़े किसी भी कार्य करने मिशन रीव लोगों की पूरी मदद करता है और कार्य पूरा करने तक आपके साथ रहता है।

आवश्यकता आकलन का प्रारूप नमूना

हमारा लक्ष्य संपत्ति प्रबन्धन की गुणवत्ता को उत्कृष्ठता के साथ ऑनलाईन सेवाओं के माध्यम से सदस्य तक पहुंचाने की है । ऐसा कोई भी क्षेत्र जो संपत्ति प्रबन्धन से संबन्धित हो उसे मिशन रीव के इस प्रभाग में शामिल किया गया है ।

क्या आपको संपत्ति से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहायता की आवश्यकता है या निम्नलिखित संपत्ति प्रबंधन सेवाओं में से किसी की आवश्यकता हैं?
Do you need assistance in solving issues related to property or any of the following property management services ?

	जमीन या किसी अन्य अचल संपत्तियों से संबंधित मुद्दे जैसे स्पष्ट शीर्षक या भूमि का सीमांकन या लंबित संपत्ति	अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का सुधार	Demarcation
Property Division	अपनी संपत्ति के शेयर्स को अलग अलग करना	अपनी संपत्ति के शेयर्स को अलग अलग करके प्लाट कटवाना	Plot Cutting
Certificates	जमीन के क्रयविक्रय के लिए हिमाचली कृषक प्रमाण पत्र बनाना	अपने प्लाट पर घर बनाने का नक्शा बनाना	
Architectural Map & Design	अपने प्लाट पर घर के नक्शे की स्थानीय निकाय से स्वीकृति बिल्डिंग प्लान में संशोधन	अपने नक्शे के लिए सभी प्रकार के दस्तावेज, एनओसी तैयार करना/एकत्र करना	
Property Sale/Purchase	किसी भी संपत्ति की बिक्री/निपटान या खरीद		

SUBMIT

कृषि बागवानी और पशुधन डिविजन

हिमाचल एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि बागवानी और पशुधन आज भी गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15 फीसदी है। हिमाचल प्रदेश में कृषि कार्यो द्वारा लगभग 69 प्रतिशत आबादी को रोजगार मुहैया हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 10.4 फीसदी भू-भाग पर नौ लाख 40 हजार लोग खेती कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में कई नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए कृषि , सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के मद में 3995 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। इन सब के बावजूद किसानों-बागवानों को जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार भी अपने उद्देश्य का 100 फीसदी प्राप्त नहीं कर पाती। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के किसानों-बागवानों तक पहुंच सके और प्रदेश के किसान कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर प्रदेश के विकास में योगदान दे सके इसके लिए मिशन रीव अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मिशन रीव के कृषि, बागवानी और पशुधन प्रभाग में किसानों और बागवानों के लिए अनेक योजनाए और सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

ऐसे काम कर रहा मिशन रीव

कृषि / बागवानी में मिशन रीव की सेवाएं

मृदा परीक्षण

मिशन रीव के तहत प्रदेश के गांवों में मृदा परीक्षण की सुविधा द जा रही है। इसके लिए गांव-गांव जाकर शिविरों का आयोजन किया जाता है और किसानों-बागवानों से मृदा के नमूने तय मानको के मुताबिक एकत्र कर उनका परीक्षण किया जाता है और रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार कर जल्द से जल्द भेज दी जाती है। इसके लिए शिमला स्थित कार्यालय में खास तौर पर मृदा परीक्षण लैब स्थापित की गई है।

जांच के लिए मृदा नमूने एकत्र करने वाले मिशन प्रतिनिधियों को कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में विशेष परीक्षण दिया गया है। बेहतर किस्म के बीज और कृषि उपकरणों का वितरण-बेहतर किस्म के बीज और कृषि उपकरण भी मिशन रीव के तहत लोगों को उनके घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के तहत भी कृषि और बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिशन रीव गांव तक पहुंचा रहा है। जिला सोलन में किसानों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले अत्याधुनिक स्प्रे पंप किसानों तक पहुंचाने में मिशन रीव अहम भूमिका निभा चुका है। इसी तरह कई अन्य आधुनिक कृषि उपकरण लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में मिशन रीव मदद कर रहा है।

रीव जैविक खाद

प्रदेश को जैविक राज्य बनाने में मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ गांव के लोगों की आर्थिक भी इस मिशन रीव के इस प्रयास से मजबूत हो रही है। बीते एक साल में मिशन रीव के तहत विभिन्न पंचायतों में 500 से अधिक किसानों को जैविक खाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया और किसानो द्वारा तैयार खाद को बाजार भी उपलब्ध करवाया गया। जिला सोलन में ऐसे कई उदाहरण है जहां किसानो ने जैविक खाद बनाकर अच्छी खासी कमाई की।

सोलन समेत अन्य जिलों में भी किसानों ने जैविक खाद बनाई। किसानों द्वारा तैयार खाद को मिशन रीव के माध्यम से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचाया गया और किसानों को उनके घर पर खाद के अच्छे दाम भी मिल गए। मिशन रीव के तहत जिला सोलन से जैविक खाद को किन्नौर लाहुल स्पीति और चंबा के दूरदराज तक पहुंचाया गया। मिशन रीव के इस प्रयास की गांव के लोगों ने खूब सराहना की।

रीव जैविक कीटनाशक

खाद के साथ साथ किसानों को मिशन रीव के तहत रीव जैविक कीटनाशक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कीटनाशक बाजार में मिलने वाले रासायनिक कीटनाशक की अपेक्षा बेहद असरकारक और हानिरहित है।

सरकारी योजनाओं का लाभ

मिशन रीव अपनी सेवाओं के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी लोगों का सहयोग कर रहा है।

किसानों को सोलर सिंचाई पंप, सोलर स्प्रे पंप, बीज वितरण में भी मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है।

पशुधन

हिमाचल में पशुधन किसानो -बागवानों की आय का प्रमुख साधन है। पहाड़ों पर अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। ऐसे में खेती करने के लिए पशुधन की भूमिका अहम है। प्रदेश के अधिकतर गांवों में आज भी खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए पशु होना जरूरी है।

इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय में भी काफी लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहां भी समस्या पशुओं की वैज्ञानिक देखरेख की जानकारी न होना और पशुउत्पादों को सही बाजार न मिल पाने की है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के प्रयास भी मिशन रीव की ओर से किए जा रहे हैं।

रीव फीड सप्लीमेंट

पशुओं की सेहत में सुधार और दुग्ध उप्तादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए मिशन रीव के तहत पशुपालकों को रीव फीड सप्लीमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। बीते एक साल में प्रदेश की लगभग हर पंचायत में रीव फीड सप्लीमेंट पहुंचाने के साथ ही पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसकी आपूर्ति की गई। सभी जगहों से इसके बेहतर परिणाम मिले हैं और पशुपालकों में इसकी मांग बढ़ी है।

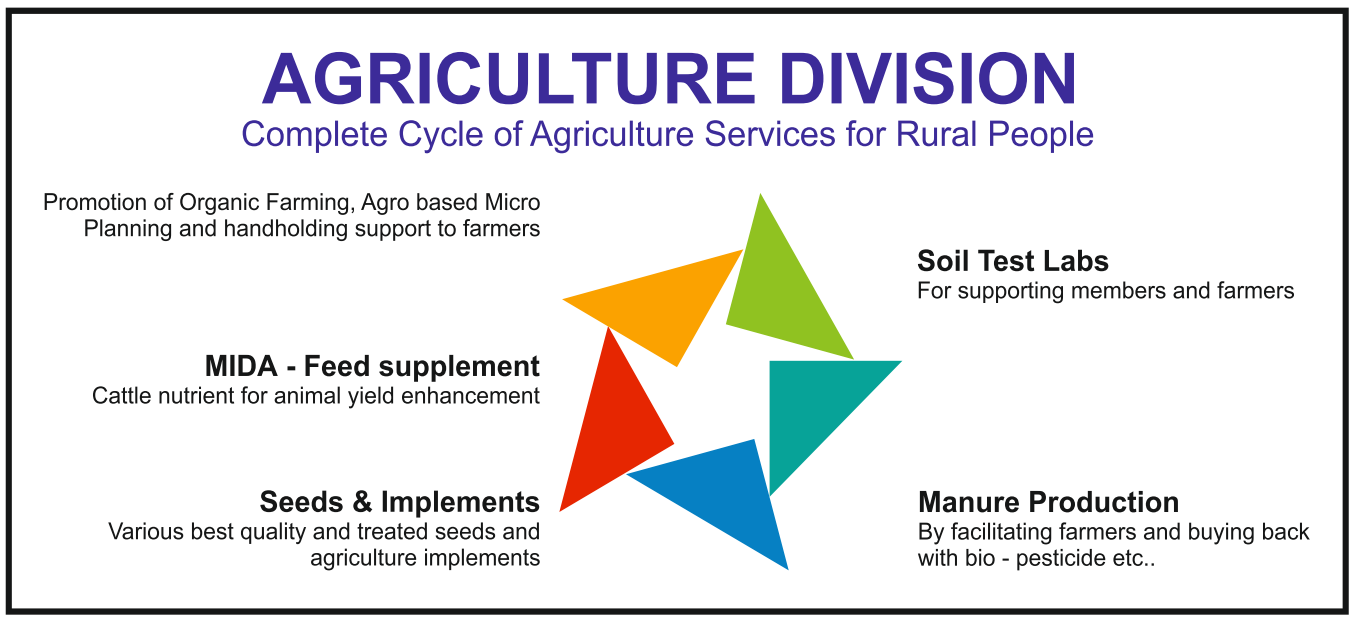

सरकारी योजनाओं का लाभ

पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी जागरूकता शिविर के माध्यम ये गांवों मे पशुपालकों तक पहुंचाया जा रहा है और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहयोग किया जा रहा है।

आगे क्या

सभी जिलों में स्थापित होगी लैब

किसानों और बागवानों को मृदा परीक्षण की सुविधा उनके घर-द्वार पर तय समय में मिले इसके लिए मिशन रीव के तहत प्रदेश के सभी जिलों में मृदा परीक्षण लैब स्थापित की जा रही है।

वर्टीकल खेती को बढ़ावा

प्रदेश में लगातार जोतों की संख्या कम हो रही है। जगह की कमी और मौसम की मार के चलते कृषि पैदावार भी कम हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए मिशन रीव वर्टीकल खेती को बढ़ावा देने की योजना पर कार्य कर रहा है। इस तरह की खेती में कम जगह पर अधिक पैदावार की जा सकती है और मौसम की मार से भी फसलों को बचाया जा सकता है। इस तरह की खेती में कम संसाधनों के साथ अच्छी आय की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है।

पूसा एस टी ऍफ आर मीटर किट निम्नलिखत मानको पर मिट्टी परिक्षण करती है

1	जैविक कार्बन	(OC)	8	प्राप्य आयरन	(Fe)
2	प्राप्य नाइट्रोजन	(N)	9	प्राप्य मैंगनीज	(Mn)
3	प्राप्य फास्फोरस	(P)	10	कॉपर	(Cu)
4	प्राप्य पोटैशियम	(K)	11	विद्युत चालकता	(EC)
5	प्राप्य जस्ता (जिंक)	(Zn)	12	पीएच	(pH)
6	प्राप्य सल्फर	(S)	13	एसिड मिट्टी के लिए चुना टेस्ट	
7	प्राप्य बोरोन	(B)	14	क्षारिक मृदा के लिए जिप्सम टेस्ट	

मृदा की पोषकता को बढ़ावा

वर्तमान में मिशन रीव के तहत किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा दी जा रही है। जल्द ही मृदा परीक्षण के बाद उसमें पाए जाने वाले पोशक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जैविक खाद का उन्नत रूप भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

घर पर बाजार

ऐसा कई बार होता है जब अच्छी फसल पैदा होने के बावजूद किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। कारण है समय पर फसलों का मंडी तक न पहुंच पाना। कई बार ढुलाई के लिए मालवाहक न मिलने से तो कई बार मजदूर न मिलने से फसल खेत में ही सड़ जाती है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए भी मिशन रीव जल्द किसानों को अपने स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। यानि मिशन किसानों से वाजिब दामों पर कृषि उत्पादों की खरीद करेगा और फिर अपनी जिम्मेदारी से उसे बाजार तक पहुंचाएगा।

ऑनलाइन कन्सल्टेंसी सुविधा

मिशन रीव के तहत जल्द ही किसानों को ऑनलाइन कन्सल्टेंसी की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। अगर किसी भी बागवान या किसान को किसी योजना के बारे में जानकारी लेनी है अथवा कृषि ,बागवानी व पशुधन से जुड़ी कोई विशेषज्ञ राय लेनी हो तो वह सीधे मिशन रीव के तहत ऑनलाइन विशेषज्ञ से इसकी राय ले सकते हैं।

जल संरक्षण

जल संरक्षण को लेकर मिशन रीव काफी गंभीर है। मिशन रीव की ओर से गांव में पंचायतों के साथ मिलकर जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन रीव जल्द ही प्राकृतिक स्त्रोतों के संरक्षण के लिए अपने स्तर पर कार्य करेगा और प्राकृतिक स्त्रोतों के रखरखाव के साथ-साथ वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कार्य करेगा।

बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन

आज के दौर में किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना वित्तीय प्रबंधन व बैंकिंग सुविधा के नहीं चल सकता। विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, स्वरोजगार से जुड़ा , कोई व्यक्ति हो अथवा किसी भी व्यापार से जुड़ा कोई व्यवसायी हो, सभी को बैंकिंग से जुड़े कार्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन गांव में लोगों के लिए बैंक से जुड़े कार्यों को कम खर्च और कम समय में आसानी से पूरा करना किसी चुनौति से कम नहीं है। लोगों की इसी समस्या को सुलझाने के लिए मिशन रीव की ओर से बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस डिविजन का निर्माण किया गया है। इस प्रभाग के तहत बैंक से जुड़े किसी भी तरह के कार्यों को एक ही छत के नीचे पूरा किया जाता है। आपको बैंक में खाता खुलवाना है, क्रेडिट / डेबिट कार्ड बनवाना है, लोन लेना है, बीमा करवाना है अथवा बैंक व फाइनेंस से जुड़ी अन्य कोई समस्या है, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस डिविजन के तहत आपकी हर समस्या का निवारण मिशन रीव करता है।

ऐसे काम कर रहा मिशन रीव

सदस्यता – सबसे पहले व्यक्ति को मिशन रीव की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मिशन रीव की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के पास तीन तरह के विकल्प मौजूद रहते हैं जिसकी पूरी जानकारी मिशन रीव के वेब पोर्टल पर मौजूद है।

आवश्कता आकलन – दूसरा चरण आवश्यकता आकलन का है। आवश्कता आकलन सदस्य आसान से प्रश्नो के उत्तर देकर कर सकता है। यह प्रश्नोत्तरी इस तरह से तैयार की गई है कि सदस्य आसानी से अपनी आवश्यकता और क्षमता के आधार पर अपनी जरूरतों को पहचान सकता है और समस्याओं का निवारण भी आसानी से हो जाता हैं।

सेवा प्रदाता टीम – आवश्यकता आकलन के बाद तीसरे चरण में सेवा प्रदाता टीम का कार्य शुरू हो जाता है। यह टीम व्यक्ति की आवश्कता के आधार पर कार्य पूरा करने के लिए काम करती है और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करती है। यह टीम कार्य पूरा करने तक व्यक्ति के साथ रहती है।

सेवा निष्पादन – सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मिशन रीव की टीम सदस्य को उसके घर तक सेवा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अगर कोई सदस्य लोन लेने का इच्छुक है और इस लोन से कोई कार्य शुरू करना चाहता है तो मिशन रीव की टीम लोन दिलवाने से लेकर सदस्य को उसके मनमुताबिक प्रोजेक्ट शुरू करने तक साथ रहती है और सभी कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाती है।

बैंकिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट के तहत ये सेवाएं हैं शामिल – बैंकिंग फैसीलिटेशन सर्विस

अगर कोई सदस्य बैंक में खाता खोलना चाहता है तो सबसे पहले मिशन रीव सर्विस एसोसिएट आपकी सुगमता के हिसाब से बैंक की जानकारी और खाता खोलने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी देगा। इसके बाद खाता खोलने के लिए सभी दस्तावेजों को तैयार करके उन्हें बैंक में जमा करवाएगा। इस तरह खाता खोलने का पूरा कार्य मिशन रीव करके देता है।

फाइनेंशल मैनेजमेंट सर्विस

खाता खोलने के बाद जमा पैसों पर मिलने वाली ब्याज की दर क्या रहेगी और किस तरह के खाता खोलने पर किस बैंक में ज्यादा लाभ मिलेगा, इन सब की पूरी जानकारी भी मिशन रीव आपको देता है और आपको बेहतर विकल्प चुनने में सहायता करता है।

बैंकिंग सर्विस सुपोर्ट

इसके तहत मिशन रीव बैंक की ओर से दी जाने वाली सभी सेवाओ को आप तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनाना है, चैक बुक इश्यू करानी है या बैंक खाते को आधार से जोड़ना है अथवा कोई अन्य औपचारिकता पूरी करनी हो तो यह सभी कार्य करने की जिम्मेदारी भी मिशन रीव निभा रहा है।

फाइनेंशल सर्विस सुपोर्ट

अगर आप किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो यह लोन आपको मिशन रीव दिलाता है। हाउस लोन, एजूकेशन लोन, पर्सनल लोन,

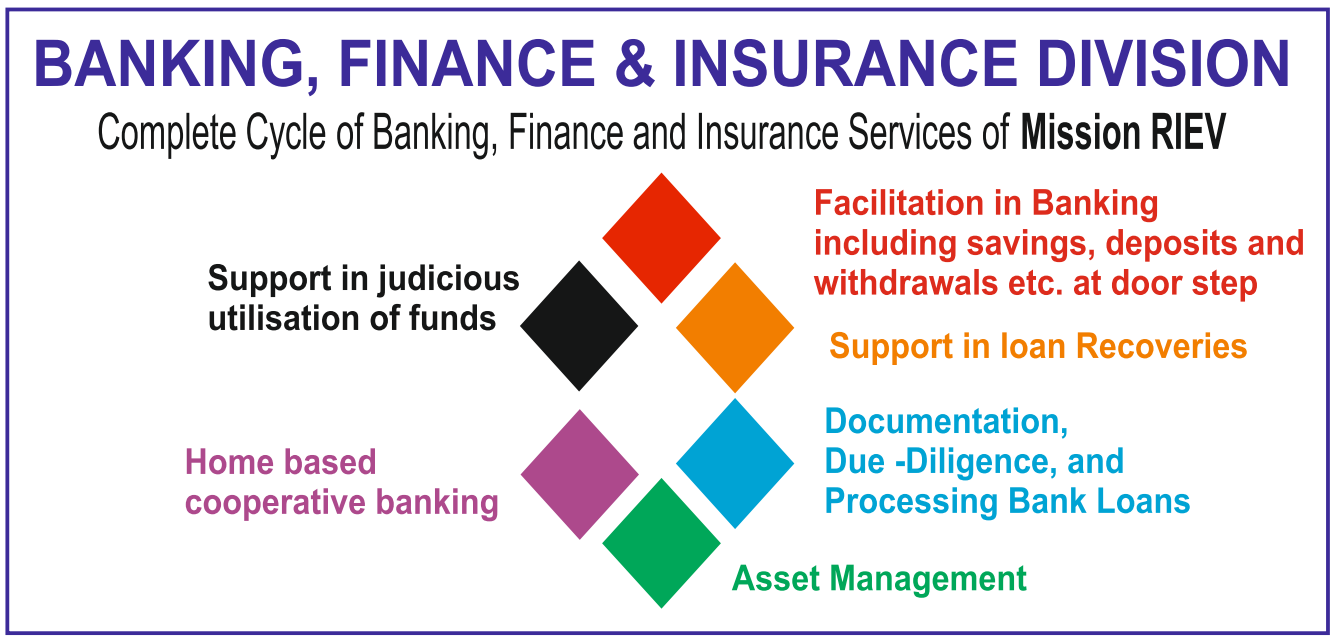

एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन, कार लोन अथवा अन्य किसी भी तरह का लोन लेना है तो यह सभी तरह के लोन बिना परेशानी के मिशन रीव आपको आपके घर पर दिलाता है। अभी तक 30 से अधिक लोगों को विभिन्न बैंकों से लोन दिलाया जा चुका है और करीब 50 लोगों ने मिशन रीव के पास बैंक से लोन दिलाने के लिए आवेदन किया है।

इन्वेस्टमेंट फैसीलिटेशन सर्विस

अगर कोई सदस्य कहीं पर धन निवेश करना चाहता है तो यहां भी मिशन रीव सहयोगी के तौर पर आपके साथ रहता है। बाजार में निवेश के बेहतर विकल्प तलाशना, सदस्य की क्षमता और आवश्यकता के हिसाब से उसकी तुलना करना और उसके बाद निवेश करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करना, यह सभी जिम्मेदारियां मिशन रीव निभा रहा है।

जीवन बीमा

प्रदेश के गांवों में आज भी अधिकतर लोगों को जीवन बीमा के महत्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। गांव में लोगों के जीवन को आर्थिक और समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी की है साथ ही SBI जनरल इंशोरेंस सेवाएं भी मिश्न रीव लोगों को देगा। अभी तक 50 से अधिक लोगों के जीवन का बीमा LIC के तहत करवाया जा चुका है और कई लोगों को एलआईसी की पॉलिसी से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा गांव गांव में लोगों को समाजिक और आर्थिक सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

कैसे सेवाऐं देगा मिशन रीव

मिशन रीव गांव-गांव में आज एक जाना जाने वाला नाम है । सरकार के सहयोगी के रुप में मिशन रीव सदैव अग्रणी भूमिका में रहा ही है लेकिन अपनी नायाब सेवाओं के माध्यम से भी लोगों तक विश्वसनीय पहुंच बनाई है । उपरोक्त बीमा सेवाओं को मिशन रीव के कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों को जागरुक करेंगें तथा उनका उनकी आवश्यकतानुसार बीमा करवाऐंगें । मिशन रीव का फील्ड स्टाफ इसे करने से पहले प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे । यानि उनको क्या करना है और पूरी प्रक्रिया को प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाऐगा। प्रशिक्षण लेने के बाद एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के साथ गांव में लोगों को जानकारी दी जाऐगी तथा इसके लिए जागरुकता शिविर आदि भी लगाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

आईआईआरडी के जनोपयोगी प्रयास मिशन रीव ने हिमाचल प्रदेश के गांवों को विभिन्न सुविधाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है। लोगों को घर-द्वार पर सुविधाओं की सरल एवं गुणात्मक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीव के कार्यकर्ता सेवाऐं दे रहे हैं। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं लोगों की आवष्यकताओं को देखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी संस्था ने मिशन रीव के माध्यम से लोगों को बीमा के दायरे में लाने का निर्णय लिया। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता कर अब यह राह भी आसान हो गई है।

आवश्यकता आकलन का प्रारूप नमूना

हमारा लक्ष्य बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन की गुणवत्ता को उत्कृष्ठता के साथ ऑनलाईन सेवाओं के माध्यम से सदस्य तक पहुंचाने की है । ऐसा कोई भी क्षेत्र जो बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन से संबन्धित हो उसे मिशन रीव के इस प्रभाग में शामिल किया गया है ।

क्या आप घर बैठे बैंकिंग सेवा प्राप्त करना चाहते हैं? Do you want to get banking service?	○ Yes ○ No
क्या आप बाजार से जुड़ी निवेश योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं जो उच्च रिटर्न प्रदान करती है? Do you want to invest in market -linked investment plan which offer higher return?	○ Yes ○ No
क्या आप को किसी भी काम के लिए ऋण लेने के लिए हमारी सहायता (प्रसंस्करण, प्रलेखन आदि) की आवश्यकता है? Do you want our assistance (in processing, documentation, etc.) to avail loan for any work	○ Yes ○ No
खाता खोलने के लिए क्या आपको सहायता की आवष्यकता है? Do you need assistance to open an account?	○ Yes ○ No
क्या आपको अपने वर्तमान बैंक की तुलना में अपने नकद जमा के लिए उच्च ब्याजदर देने वाले बैंक में अपने फंड को स्थानांतरित करने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता है? Do you need our assistance to transfer your fund to a bank offering a higher interest rate for your cash deposits than your present bank?	○ Yes ○ No SUBMIT

संस्थागत सहयोग एवं क्षेत्र अभिग्रहण सेवा प्रभाग

मिशन रीव के अंतर्गत तीन नए प्रभागों का गठन किया गया है जिसमें संस्थागत सहयोग एंव क्षेत्र अभिग्रहण सेवा प्रभाग एक है। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य संस्थानों को विभिन्न प्रकार की तकनीकि एवं अन्य समस्त प्रकार की सेवाओं के प्रति सहयोग करेगा। हमारे देश का मूल आधार हमारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर निर्भर है। इन संस्थानों में शिक्षा से लेकर संस्थानों में प्रशिक्षण आदि के लिए तकनीकि सहयोग की बड़ी आवश्यकता रहती है। मिशन रीव का ये प्रभाग इसमें समस्त समाधान की प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए इस प्रकार से सेवाऐं देगा

- समिति, कृषि उत्पाद संस्थाएं, ग्राम पंचायत, मंदिर, युवक मण्डल, महिला मण्डल, कंपनी, कोओपरेटिव समीतियों एवं फर्म आदि का आवश्यकता विश्लेषण करना
- उपरोक्त हेतु भविष्य की योजना निर्माण, व्यवसायिक योजना क्रियान्वयन, निगरानी एवं मुल्यांकन, अनुसंधान योजना निर्माण, अंकेक्षण, वैधानिक एवं नियामक (रेगुलेटरी) अनुपालन तथा तकनीक का अभिग्रहण आदि इसमें शामिल है।

MISSION RIEV
Ruralising India - Empowering Villages

अप्रवासी भारतीय सहयोग सेवा प्रभाग

अप्रवासी भारतीयों के लिए मिशन रीव अब अपनी सेवाओं को प्रदान करने हेतु इस प्रभाग में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ समर्पित है। अप्रवासी भारतीयों के परिजनों और रिश्तेनातेदारों के लिए हमारे इस प्रभाग में समस्त सेवाओं का समावेश है ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अप्रवासी भारतीयों को देश में व्यवसाय से लेकर अन्य सहयोग हेतु इसी प्रभाग की सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है।

- अप्रवासी भारतीयों के परिवार के लोगों तथा समस्त उन लोगों के लिए जो अप्रवासी भारतीयों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है, उनके लिए इस प्रभाग से सेवाओं को प्रदान करना।
- अप्रवासी भारतीयों की वैधानिक समस्याओं/कार्यों को तीव्रता से सुलझाने और निदान हेतु विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान करना।
- निवेश आदि की योजनाओं में मिशन रीव इसी प्रभाग के माध्यम से सेवाऐं प्रदान करते हुए सहयोग देगा।
- व्यवसाय विकास हेतु भी अप्रवासी भारतीयों के लिए इसी प्रभाग में मिशन रीव सहयोग देगा।
- उपरोक्त समस्त योजनाओं में अप्रवासी भारतीयों को सहयोग देते हुए अन्य सेवाओं में भी विस्तार देना।

MISSION RIEV
Ruralising India - Empowering Villages

चुनावी सेवा प्रभाग

भारत में चुनावों का मौसम बारहमासी है। कभी न कभी किसी न किसी राज्य में चुनाव प्रक्रिया चल ही रही होती है। साथ ही आज प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सर्वेक्षण एवं एक्जिट पोल आदि की भी बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में पारदर्शी एवं सटीक सर्वेक्षण आदि में मिशन रीव इसी प्रभाग की सवाओं के माध्यम से सहयोग देगा। साथ ही घोषणापत्रों को बनाने से प्रचार आदि तक तकनीकि सहयोग के लिए भी इसी प्रभाग में समुचित व्यवस्था है। इस सेवा प्रभाग में शामिल हैं।

- आधारभूत एवं सटीक आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मिशन रीव में इसी प्रभाग में सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं।
- उत्साही एवं दक्ष प्रतिनिधियों की पहचान हेतु मुल्यांकन आधारित सर्वेक्षण करना इसी प्रभाग का उत्तरदायित्व है।
- विभिन्न स्तरों पर लोगों के लिए चुनावी घोषणपत्र आदि को बनाने के लिए सहयोग करना भी इसी प्रभाग में आता है।
- सामाजिक मीडिया प्रबंधन आदि में भी इसी प्रभाग में सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं।

MISSION RIEV
Ruralising India - Empowering Villages

राज्य सरकार की विकासात्मक योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने में स्वैच्छिक सेवाएं

मिशन रीव सेवा कर्मी द रीव टाइम्स में प्रकाशन के बाद योजनाओं की जानकारी को गांव–गांव तक पहुंचा रहे हैं

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना

पुष्प क्रांति योजना के तहत फूल उगाने के लिए उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस बनाने और पुष्प की खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है।इसके साथ ही वित्तिय मदद दी जाती है। हिमाचल प्रदेश का वातावरण पुष्प उगाने के लिहाज से भी अनुकूल है, इस वजह से सरकार युवाओं को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। निजी क्षेत्र की पुष्प विपणन क्षेत्र में सहभागिता व कृषि संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुष्प क्रांति योजना से राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। इसमें कुशल एवं अकुशल, दोनों तरह के लोगों के लिए रोजगार के मौके बन सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना (हिम केयर)

हिमाचल में लोगों को बेहतर और हिमाचल में लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी ही एक योजना है हिम केयर। इस योजना के तहत मात्र एक हजार रूपये सालाना का प्रीमियम देकर सरकारी अस्पतालों में पांच लाख तक का ईलाज निषुल्क करवाया जा सकता है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर पर शुरू की गई हिम केयर योजना की जानकारी देने जा रहे हैं।

डेयरी एंटप्रेन्यूरशिप डिवेलपमेंट स्कीम

ग्रामीण क्षेत्रों लोगों को पशुधन के प्रति आकर्षित करने और दूग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2010 में दूध गंगा योजना शुरू की गई। लेकिन 2013 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब योजना को शुरू करने के लिए हरी झंडी दी, लेकिन दूध गंगा योजना का नाम बदलकर डेयरी एंटप्रेन्यूरशिप डिवेलपमेंट स्कीम रखा गया है। हिमाचल में सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको इस योजना के तहत सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता और इस योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। 2010 में शुरू की गई इस योजना में वर्ष 2014–15 में केंद्र सरकार ने काफी फेरबदल किया गया।

अनुभव योजना

हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से मिलने का समय और तारीख जैसी सुविधा मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए अनुभव योजना शुरू की गई है। वास्तव में यह एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। हिमाचल के नागरिक अनुभव योजना के तहत घर बैठे डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। यह व्यवस्था एक टोकन के जरिये होती है जिसमें आप डॉक्टर से समय लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से उनसे दिखाने जा सकते हैं। अनुभव योजना अभी कुल्लु जिला अस्पताल में शुरू की गई है।

स्वरोजगार के लिए हिमाचल सरकार से मदद

अगर कोई गरीब महिला छोटा-मोटा कारोबार करना चाहती हो उन्हें हिमाचल सरकार से स्व रोजगार सहायता योजना में मदद मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को अपना रोजगार करने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से स्वयं रोजगार सहायता योजना शुरू की है। स्वयं रोजगार सहायता योजना में ऐसी महिलाओं को 2500 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है जिनके परिवार की सालाना आय 35,000 रुपये से कम हो। इस आमदनी में हालांकि मनरेगा से हुई कमाई शामिल नहीं है।

युवा आजीविका योजना

अगर आप भी अपना काम करना चाहते हैं और पूंजी की दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश सरकार की युवा आजीविका योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के हिमाचल सरकार ने स्वरोजगार स्कीम युवा आजीविका योजना शुरू की है। युवा आजीविका योजना नाम की इस स्कीम में सरकार बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी और उसके ब्याज पर पहले साल 8 प्रतिशत की सब्सिडी देती है।

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना

हिमाचल में महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको प्रदेष सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही दो महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि योजनाओं के लिए क्या पात्रता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश मे विधवा पुनः–विवाह योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी विधवा पुन :- विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुन :- विवाह में मदद करना है और विधवाओं के साथ पुनर्विवाह करने के लिए पुरुषो को प्रोत्साहित करना। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 50, 000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 20,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 30,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

एक फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से पेष किए गए बजट में किसानों और निचले तबके के लोगों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है। इसमें किसानों के लिए निधि योजना शुरू की गई तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी पहली बार पेंशन योजना की शुरूआत की गई। विषेशज्ञों का कहना है कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भविश्य में वित्तिय असुरक्षा की भावना से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे कि इस योजना का लाभ लेने के पात्र लोग कैसे योजना से जुड़कर अपना भविश्य सुरक्षित कर सकते हैं- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत 15 फरवरी से हो चुकी है यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जिसकी ब्याज दर को संगठित क्षेत्र के पेंशन फंड के ब्याज 8.55 फीसदी के करीब रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना बढ़ाएगी हिमाचल में मिठास

प्रदेश में शहद के व्यवसायिक उत्पादन में क्रांति लाने के लिए उद्यान विभाग ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना शुरू की है। मधुमक्खी से जहां प्रदेश में मीठा कारोबार बढ़ेगा, वहीं पहलीनेशन से यहां फल, फूल, दलहन, तिलहन की उत्पादकता व गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्रदेश में उद्यान विभाग के माध्यम से मधु विकास योजना चलाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक हम आपको इस योजना की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। शहद प्राचीनकाल से ही मनुष्य की जीविकापार्जन का साधन रहा है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो इकाइयां विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड है इसे NCSBS संगठन के रूप में जाना जाता है। यह गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय के क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करता है। इस लक्ष्य के साथ मुद्रा को सिडबी की एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित कर शुरू किया गया है। योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला - स्वरोजगार के लिए आसान लोन उपलब्ध करवाना और दूसरा - छोटे उद्यमों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सामने लाना।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केन्द्र की भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं के नाम पर दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार वर्ष 2020 तक देश में 8 करोड़ से अधिक BPL और गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018–19) तक देश भर में 5.5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

शिक्षा लोन योजना

अधिकतर देखा जाता रहा है की कई प्रतिभाशाली छात्र पैसे न होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते है देश में इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में एजुकेशन लोन योजना को शुरू करने का एलान किया था। इस योजना के अंतर्गत, अब कोई भी छात्र जो पढ़ना चाहता है परन्तु वह पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाता है अब वह छात्र भी अपनी शिक्षा के लिए लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। आज हम आपको अपने इस लेख में विस्तार से बताएंगे की कैसे आप इस अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले सकते है।

शिक्षा लोन योजना

अधिकतर देखा जाता रहा है की कई प्रतिभाशाली छात्र पैसे न होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते है देश में इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में एजुकेशन लोन योजना को शुरू करने का एलान किया था। इस योजना के अंतर्गत, अब कोई भी छात्र जो पढ़ना चाहता है परन्तु वह पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाता है अब वह छात्र भी अपनी शिक्षा के लिए लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है।
आज हम आपको अपने इस लेख में विस्तार से बताएंगे की कैसे आप इस अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले सकते है।

गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515

हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एक षांत राज्य के तौर पर जाना जाता है। लेकिन 2017 में हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक बहुत ही बुरी घटना घटी थी। इस घटना में कोटखाई की एक छात्रा के साथ दुश्कर्म करने के बाद बेहद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के तुरंत बाद राज्य में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को भारी मतों से विजय मिली। नई सरकार ने हिमाचल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515" की शुरूआत की। इसके साथ ही राज्य में क्राइम को रोकने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 भी शुरू की गई।

मुख्यमंत्री लोक भवन योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सामुदायिक सदभाव को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक भवन योजना लांच की है। लोक भवन योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में तीस लाख रुपये की लागत से एक सामुदायिक भवन बनाया जाता है। इलाके के सांसद और विधायक द्वारा सामुदायिक भवन के लिए योगदान भी स्वीकार किया जाता है। इसके बाद भवन का एरिया और बड़ा हो सकता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक भवन योजना के लिए साल 2018–19 के बजट में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

वन समृद्धि – जन समृद्धि योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आबादी की आमदनी बढ़ाने के लिए वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के जरिये ग्रामीण लोग औषधीय पौधे की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हिमाचल में जहां फसलों पर जंगली जानवरों की मार है वहां पर औषधीय खेती एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कुछ समय पहले ही वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना शुरू की गई है।

बेटी है अनमोल

बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक की छात्राओं को छात्रवृति देने का प्रावधान तो है ही, साथ ही बेटी के जन्म पर एफडी कराने का भी प्रावधान है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निर्देशों के तहत-गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और जच्चा-बच्चा (मां व संतान) को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। 01 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लांच किया था। इसके माध्यम से हर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को 6000 रुपए तक आर्थिक मदद दी जाती है। देश के सभी जिलों में इसे लागू किया गया है। Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana का संचालन आंगनवाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से होता है।

केन्द्र सरकार की विकासात्मक योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में स्वैच्छिक सेवाएं

मिशन रीव सेवा कर्मी द रीव टाइम्स में प्रकाशन के बाद योजनाओं की जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं

सोलर चरखा मिशन योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना की षुरूआत जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोलर चरखा मिशन के नाम से की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पहले जहां इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लिए था वहीं अब इस योजना में लोन की रकम बढ़ाकर शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को भी दायरे में लाया गया है। पहले लोन की रकम 56 से 6 लाख रुपए तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है।

लघु उद्योग

59 मिनट में 1 करोड़ का ऋण

लघु एवं मझोले उद्यम को सरकार की ओर से तोहफा

अब मध्यम, छोटे और लघु उद्यमों के लिए 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के लोन के आड़े आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। इसके अलावा पात्र संगठन, जो माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत हैं, को अब 1 करोड़ रुपये की सीमा में अतिरिक्त कर्ज पर ब्याज दर में 2÷ ब्याज सहायता दी जाएगी।

रियायती वित्तपोषण योजना

विदेश की रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय प्रतिष्ठानों को श्रय देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रियायती वित्त योजना (Concessional Financing Scheme & CFS) के पहले विस्तार की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अवसरंचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय निकायों को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है।

किसान विकास पत्र योजना : ब्याज दर व नियम

डाकघर की किसान विकास पत्र बचत स्कीम पर फिलहाल 7.7 प्रतिशत ब्याज मिलती है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2018 से लागू है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2018 के अंत में भारत सरकार ने कई लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में बढोतरी की है। इसमें किसान विकास पत्र की भी ब्याजदर पिछली तिमाही की 7.3 प्रतिशत से बढाकर 7.7 प्रतिशत कर दी गई है। इसके पहले 1 जनवरी 2018 से 30 सितंबर 2018 तक किसान विकास पत्र पर 7.3 प्रतिशत ब्याज ही लागू थी। इस दौरान की तीन तिमाहियों, जनवरी - फरवरी - मार्च, अप्रैल - मई - जून, और जुलाई - अगस्त - सितंबर की तिमाहियों के लिए किसान विकास पत्र की ब्याज दर समान स्तर पर 7.3 प्रतिशत ही बनी रही थी।

स्वदेश दर्शन योजना

स्वदेश दर्शन योजना जनवरी, 2015 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वदेश दर्शन योजना' का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2014-15 के बजट में स्वदेश दर्शन योजना के प्रारंभ की घोषणा की गई थी। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम इस बार स्वदेश योजना की जानकारी आपको दे रहे हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

गोकुल ग्राम देशी पशु केंद्र और अधिनियम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए केंद्र के रूप में काम कर रहा है और गोकुल ग्राम मूल प्रजनन इलाकों और शहरी आवास के लिए मवेशियों के पास महानगरों में स्थापित है। गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है। 1000 जानवरों की क्षमता वाले इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादक और अनुत्पादक पशुओं का अनुपात 60:40 का है। गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चारा उत्पादित करने के लिए बनाये गए हैं। गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है।

स्त्री स्वाभिमान योजना

महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई है। इसका नाम है स्त्री स्वाभिमान योजना। हमारे देश में आज भी कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के समय अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरुक बनाना है। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया है। यह मिशन कुपोषण, एनीमिया, जन्म के समय कम वजन और वृद्धि में रुकावट की समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (जन्म के 6 महीने बाद), साथ ही ऐसी महिलायें जिनके बच्चे (6 महीने से 3 वर्ष के बीच) के हैं वे घर के लिए राशन ले सकती हैं। इस योजना से पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

कृषोन्नति योजना हरित क्रांति

सरकार ने देश में चल रही 'हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना' की समय सीमा को और बढ़ा दिया है और अब ये योजना साल 2020 तक हमारे देश में जारी रहेगी। छतरी योजना यानी 'अम्ब्रेला स्कीम' 'हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना' के अंदर ग्यारह योजनाओं को शामिल किया गया है और ये सभी योजनाएं हमारे देश के किसानों के विकास और उनकी इनकम में वृद्धि से जुड़ी हुई हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना

'हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना' हिमाचल राज्य के मेधावी छात्रों के लिए चलाई जा रही हैं। सरकार का मानना हैं कि राज्य में बहुत से ऐसे गरीब होनहार छात्र हैं जो पैसों की कमी के कारण लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं। आजकल के समाज में कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ज़रुरी हो गया हैं। लेकिन गरीबी के कारण कई छात्र लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना

'हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना' हिमाचल राज्य के मेधावी छात्रों के लिए चलाई जा रही हैं। सरकार का मानना हैं कि राज्य में बहुत से ऐसे गरीब होनहार छात्र हैं जो पैसों की कमी के कारण लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं। आजकल के समाज में कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ज़रुरी हो गया हैं। लेकिन गरीबी के कारण कई छात्र लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं।

हिमाचल प्रदेश मे मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों का कल्याण है। अनाथ बच्चा वह है जिसका माता पिता मृत, अज्ञात है, या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया है, इस तरह के बच्चों की देखभाल और रखरखाव के लिए यह योजना हैं। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार को मुफ्त आश्रय, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और पेशेवर मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं।

स्टार्ट-अप इंडिया

भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी Startup India का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया है, की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गयी थी। ये मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिये एक प्रभावी योजना है।

ग्रामीण भंडार योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सौलर चरखा मिशन योजन की शुरुआत की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सौलर चरखा मिशन योजन की शुरुआत की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

Sansad Adarsh Gram Yojana के तहत गाँव के लोगों के जीवन में नए सुधार आयेंगे इस वजह से उन्हें नयी तकनीक और सुविधाऐं प्राप्त होंगी जिससे वह और तरक्की कर पाएंगे। यह योजना बेहद ही अद्वितीय और लचीली भी है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और इतना ही नहीं वह कुछ सेवाओं का मूल्य बढ़ाना चाहते थे, जैसे की अन्त्योदय, लड़कों और लडकियों में समानता, महिलाओं की गरिमा बनाये रखना, स्वच्छता आदि गांव के लोगों में और गाँव में आने वाला परिवर्तन सबके लिए मिसाल होना चाहिए।

आईए जानते हैं हिमाचल की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत

हिमाचल प्रदेष में इस योजना को अभी और गति पकड़ी होगी। टीम रीव की पड़ताल में इस योजना को धीमी गति से ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक कारण तो अनापत्ति प्रमाण पत्रों की कमी तथा दूसरे शहरी क्षेत्रों में ज़मीन का न होना है। क्योंकि जिनके पास शहर में ज़मीन है, वो तो ग़रीब कम ही है और जो किराए दार है उनके पास आय के स्रोत वांछित आंकड़े को भी पार कर देते हैं यानि उनकी वार्षिक आय ३ लाख से अधिक होती है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट की शुरुआती योजना है। मेक इन इंडिया के तहत बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना को 2015 में नई नेशनल स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रिन्योरशिप पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि युवा रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों पर निर्भर न रहते हुए खुद को इतना सशक्त करें कि अपने कौशल के आधार पर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए पहले इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी इस अंक में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मिशन रीव सेवा कर्मियों ने निभाई आपदा रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका

रीव जागरूकता अभियान से टला था रेबीज का बड़ा संकट

पागल कुत्ते द्वारा काटी गई गाय के दूध से था रोग फैलने का खतरा

प्रशासन और विभाग ने भी की सराहना

क्या कहती हैं हैड आशा वर्कर अनु कौशल

हैड आशा वर्कर चंबा अनु कौशल का कहना है कि जब गाय की मौत के बात रेबीज का खतरा गांव में पैदा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में मिशन रीव ने पूरा सहयोग दिया और उन लोगों को भी जागरूक किया जो दूरदराज के क्षेत्र में रहते हैं। इस दौरान मिशन रीव जिला संयोजक और उनकी टीम ने गांव के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया।

चंबा के दूरदराज गांव थला के लोग उस समय सहम गए थे जब उन्हें पता चला कि गांव पर रेबीज का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन संकट की उस घड़ी से निपटने में मिशन रीव ने जो योगदान दिया उसकी सराहना आज भी थला गांव के लोग खुले मन से करते हैं।

दरअसल, थला समेत आसपास के गांव में रेबीज प्रभावित एक गाय के दूध से बनी कढ़ी और छाछ के सेवन से रेबीज फैलने का खतरा पैदा हो गया था। इस संभावित खतरे और उसे निपटने के लिए मिशन रीव ने जागरूकता अभियान चलाया था। अब गांव के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मिशन रीव की टीम ने जिला संयोजक राकेश शर्मा की अगुवाई में उस समय के प्रभावित गांवों का दौरा किया और लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

रीव टेलीमेडिसन ...घर से जांच, घर तक उपचार

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन रीव की अद्वितीय पहल

छह माह में पांच हजार लोगों की घर पर स्वास्थ्य जांच

गांवो में शुगर के मरीज बन रहे लोग

क्या कहते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य बी के अग्रवाल

मिशन रीव के तहत जनऔषधि केन्द्र शिमला का उद्घाटन करने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बी के अग्रवाल ने बताया कि जनऔषधि केन्द्रों के खुलने से गांव में लोगों को सस्ती एवं गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध हो पाएगी, जिसमें आईआईआरडी ने प्रशंसनीय कार्य किया है । उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऐसी संस्था की कमी लंबे समय तक देखी गई जो योजनाओं को धरातल पर लागु करने और नए प्रयासों के साथ सामने आए । प्रदेश में इस कमी को आईआईआरडी ने पूरा किया हैं । जनऔषधि केन्द्रों के संचालन एवं अन्य औपचारिकताओं में सरकार संस्था को सहयोग करेगी । इससे न केवल सेवाओं की सुलभता आम जनता को होगी बल्कि संस्था के रोजगार के लक्ष्य से प्रदेश की आर्थिकी में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकेगा ।

विदेशों में भी रीव की मांग से इसकी सार्थकता पर लगी मुहर

यू एन में मिशन रीव की वाहवाही

अफ्रीकन देशों के प्रतिभागियों से होगी रीव पर चर्चा

टीम आईआईआरडी ग्लोबल प्लैटफॉर्म जिनेवा में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव

ज़ांबिया की मंत्री Hon. Sylvia Bambala Chalikosa के साथ अफ्रीकन देशों में मिशन रीव को ले जाने की चर्चा के बाद संयुक्त छायाचित्र

हिमाचल ने कहा एक साथ ... ज़िंदगी जियें-नशा नहीं

आईआईआरडी के नशामुक्त हिमाचल अभियान ने 5 सितंबर को पूरे प्रदेश में जनमानस को जोड़ा

विद्यालयों में प्रतियोगिताऐं और युवा, महिला मंडलों में कार्यक्रम हुए आयोजित

क्या कहते हैं अभियान के संचालक एवं प्रबन्ध निदेशक

नशामुक्त हिमाचल अभियान 'ज़िंदगी जियें–नशे को नहीं' के प्रणेता एवं संचालक व प्रबन्ध निदेशक आईआईआरडी डॉ0 एल सी शर्मा ने इस अभियान की बारीकियों को सामने रखते हुए बताया कि इस अभियान के चार चरण है तथा यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण रहा जिसमें पूरे हिमाचल को शामिल किया गया था। सैंकड़ों स्कूलों के बच्चों ने इसमें विभिन्न माध्यमों से शिरकत की तथा राज्यस्तर की इस संभाषण प्रतियोगिता तक स्थान बनाया। इसके बाद दूसरे चरण पर अभियान आरम्भ किया जाएगा जिसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने भी हरसंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अलावा अब युवाओं को फोकस कर समस्या के निदान तक पंहुचने का संस्था प्रयास करेगी। इसके लिए खाका तैयार किया जा चुका है ।

आईआईआरडी की सेवाऐं प्रशंसनीय : महापौर

शिमला नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने आईआईआरडी की सेवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इस संस्था ने स्वयं को प्रदेश में अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जागरुकता और बदलाव के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी संस्था के अनेक कार्यक्रमों में वो शिरकत कर चुकी हैं तथा मिशन रीव और आईआईआरडी की गतिविधियों को समीप से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। नशे जैसी गंभीर चुनौती को स्वीकार कर इस संस्था ने प्रदेश भर में अभियान के माध्यम से अच्छी पहल की है। नगर निगम शिमला इस अभियान में हरसंभव सहयोग के लिए तत्पर है।

जैविक खाद से किसान होगें खुशहाल

पूरे हिमाचल के किसानों तक आईआईआरडी करेगा डि-कंपोजिंग रीव जैविक खाद की आपूर्ति

आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित

आईआईआरडी की एक और बड़ी उपलब्धि

उड़ीसा में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बना रही आईआईआरडी

केंद्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने किया शिलान्यास

आईआईआरडी लगातार दूसरी बार सीएसआर में नंबर वन

बेहतरीन ई–शिक्षा प्रणाली में लहराया परचम

आईआईआरडी ने सीएसआर के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। लगातार दूसरी बार 'सर्वश्रेष्ठ एनजीओ' का खिताब हासिल किया है। संस्था ने इस बार यह उपलब्धि **वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम** के तहत बेहतरीन ई शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में हासिल की है ।

महिला सशक्तिकरण में संस्था की उड़ान

दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त करते आईआईआरडी के (दांए से बांए) प्रबन्ध निदेशक डॉ. एल.सी. शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा, रीता वर्मा , महरीन इकबाल ,और आर के सिंह

मिशन रीव की उड़ान अब सात समंदर पार भी

जिनेवा में रीव पर होगी चर्चा, पहले भी यूएन में बज चुका है डंका

आईआईआरडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस् की बैठक भी पहली बार देश से बाहर जिनेवा में समस्त सेवाकर्मियों के अथक प्रयासों एवं जनमानस का प्रतिफल : डॉ0 एल सी शर्मा

एक छोटे से क़दम से जो यात्रा आईआईआरडी ने आरम्भ की थी उसका इस प्रकार आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए संस्था और मिशन रीव से जुड़ें हज़ारों सेवाकर्मियों का अथक प्रयास सदैव सराहनीय है तथा प्रदेश और पूरे देश में संस्था से जुड़ें सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग इस कामयाबी की नींव है। शीघ्र ही भारत के अलावा विदेशों में इससे भी बड़ी उपलब्धियों पर पूरी निष्ठा से सेवाऐं दी जाऐगी। मैं संस्था की ओर से इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई देता हूं।

विकास खण्ड मशोबरा की 48 पंचायतों में मिशन रीव की धमक

लोगों से भी गांव में हुआ संपर्क / युवा मंडल, महिला मंडलों के साथ हुई चर्चा

उत्तर प्रदेश में आईआईआरडी का सराहनीय क़दम

कौशल विकास योजना में युवाओं को मिला रोजगार

भारत के स्मार्ट गांव के लिए मिशन रीव हो सकता है मॉडल

दिल्ली के प्रगति मैदान में मिशन रीव पर प्रस्तुतिकरण

आईआईआरडी को मिला उत्कृष्ट एनजीओ ऑफ सीएसआर टाइम्स का राष्ट्रीय पुरस्कार

झारखण्ड में रुपांतरण परियोजना की सफलता पर आईआईआरडी टीम ने दिल्ली में प्राप्त किया पुरस्कार

उत्तर प्रदेश में कौशल विकास में आईआईआरडी दे रहा प्रशंसनीय सेवाऐं

प्रशासनिक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र

कौशल विकास से खुले रोज़गार के द्वार मिशन की सेवाओं को सराहां

योगी आदित्यनाथ ने संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों के प्रशिक्षुओं को प्रदान किए रोज़गार प्रमाण पत्र

आसाम में नई उड़ान–दिल से सेवा दिल से भुगतान

मिशन रीव अब आसाम में भी देगा सेवाऐं

Towards Disaster Risk Reduction and Making Societies Resilient

IIRD Board participating UN Global Platform Geneva as part of ARISE India

राज्य स्तरीय नशामुक्त अभियान संस्था का प्रशंसनीय प्रयास :शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश भर से आए प्रतियोगी विद्यार्थियों को किया सम्मानित

रीव फीड सप्लिमेंट अब देश के बाहरी राज्यों में भी बिकेगी

हरियाणा और पंजाब में डेयरी फार्म की मिली सराहना

पंजाब और हरियाणा में गोशाला से जन सेवा तक

रीव फीड सप्लिमेंट और जैविक खाद को मिल रही सराहना

गोसेवकों ने कायम की मिसाल...मिशन रीव का मिलेगा साथ

विशेष कला ज़रदोज़ी में आईआईआरडी की सराहनीय पहल

उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों युवाओं को मिले रोजगार के अवसर

आईआईआरडी बना अब एनएसडीसी का साझेदार

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

हिमाचल के युवाओं का हुनर तराशेगा आईआईआरडी

हिमाचल में पांच केंद्रों पर तीन सौ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य

बाहरी राज्यों में तीन हजार से अधिक अभ्यर्थियों को किया प्रशिक्षित